Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-19, अंक-22 16-30 नवंबर, 2024 (पाक्षिक) ₹20

'झारखंड के उज्ज्वल भविष्य का रास्ता केवल कमल की सरकार है'

झारखंड एवं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव

आपका हर एक वोट विकास की गारंटी और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा

विश्रामपुर विधानसभा (झारखंड) में 09 नवंबर, 2024 को आयोजित विशाल रैली में जनाभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

लाजपत नगर (नई दिल्ली) में 27 अक्टूबर, 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण

जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (पटना) पर 07 नवंबर, 2024 को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते बिहार भाजपा के नेतागण

रांची (झारखंड) में 03 नवंबर, 2024 को विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 'संकल्प पत्र' जारी करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

महाराष्ट्र में 08 नवंबर, 2024 को एक विशाल रैली को संबोधित करने से पूर्व कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

चतरा विधानसभा (झारखंड) में 09 नवंबर 2024 को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है भाजपा : नरेन्द्र मोदी**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 नवंबर, 2024 को झारखंड में दो जनसभाओं को संबोधित किया। गढ़वा में लोगों की भारी भीड़ को...

08 **एक मंत्र याद रखना है हम एक हैं, तो सेफ हैं : नरेन्द्र मोदी**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवंबर, 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित दो जनसभाओं को...

11 **झारखंड को भाजपा के डबल इंजन की आवश्यकता है: जगत प्रकाश नड्डा**
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 9 नवंबर, 2024 को रांची में डॉक्टरों से...

14 **भाजपा अन्य पार्टियों की तरह केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि संकल्प लेकर उन्हें पूर्ण करती है : अमित शाह**
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 3 नवंबर, 2024 को रांची में आगामी...

29 **'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' न केवल नाम से बल्कि अपने निर्माण में भी एकता का प्रतीक है**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में 'स्टैच्यू ऑफ...

लेख

भारत के रतन का जाना.../ **नरेन्द्र मोदी** 22
भारत की रक्षा क्रांति उड़ान भर रही है! / **नरेन्द्र मोदी** 25
टीकाकरण कार्यक्रम को सार्वभौमिक बनाने के लिए डिजिटल प्रयास / **जगत प्रकाश नड्डा** 30

श्रद्धांजलि

जम्मू-कश्मीर के विधायक देवेन्द्र सिंह राणा नहीं रहे 23

अन्य

झारखंड के विकास, अस्मिता के बचाव और उज्ज्वल भविष्य का रास्ता केवल कमल की सरकार है : जगत प्रकाश नड्डा 10
झारखंड में झामुमो-कांग्रेस-राजद ने जनता को झूठे आश्वासन देकर गुमराह किया 12
डबल इंजन की भाजपा सरकार महाराष्ट्र को सबसे बेहतर राज्य बनाने का कार्य करेगी: अमित शाह 13
'महाराष्ट्र में जब भी भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की सरकार बनती है, तो यह आगे बढ़ता है' 16
'वन रैंक वन पेंशन' योजना से 25 लाख से अधिक भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिला लाभ 18
2024-25 के दौरान 1647.05 लाख टन रिकार्ड खरीफ खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान 20
मोदी स्टोरी 24
कमल पुष्प 24
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस- झूठे वादों की एक अंतहीन गाथा 26
'मन की बात' 32

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

महाराष्ट्र के मेरे परिवारजनों ने विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों को अभूतपूर्व जीत दिलाने का दृढ़निश्चय कर लिया है।

(07 नवंबर, 2024)

जगत प्रकाश नड्डा

हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले पांच साल में नक्सलवाद और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दिया है। घुसपैठियों ने हमारे आदिवासी भाई-बहनों की भूमि को हड़पने का काम किया है।

(09 नवंबर, 2024)

अमित शाह

अघाड़ी गठबंधन का एकमात्र उद्देश्य सिद्धांतों से समझौता कर किसी भी तरह सत्ता प्राप्त करना है। वहीं एनडीए का उद्देश्य शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलकर महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है।

(10 नवंबर, 2024)

राजनाथ सिंह

झारखंड की जनता को मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि आप यहां सत्ता परिवर्तन कर दीजिये, उसके बाद हम यहां व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे।

(05 नवंबर, 2024)

मनोहर लाल

आज हाइड्रो पावर पॉलिसी के मसौदे की व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वर्तमान जलविद्युत क्षमताओं एवं भविष्य में जलविद्युत क्षमता के विस्तार जैसे विषयों पर चर्चा हुई। हमारे प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग; देश के सतत एवं ऊर्जा-सुरक्षित भविष्य की कुंजी है।

(30 अक्टूबर, 2024)

शिवराज सिंह चौहान

आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी देने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय एफसीआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार!

(6 नवंबर, 2024)

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
संविधान दिवस (26 नवंबर)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

संपादकीय

डबल इंजन की सरकार विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी

झारखंड एवं महाराष्ट्र में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होते ही चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। विभिन्न राजनैतिक दल मतदाताओं से समर्थन मांगने के लिए प्रचार अभियान में लगे हैं। जन-जन के बीच भाजपा के प्रति अथाह उत्साह का अनुमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं की चुनावी सभाओं, रैलियों एवं रोड शो में उमड़े भारी जनसमूह से लगाया जा सकता है। लोग बड़ी संख्या में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में बाहर निकल रहे हैं तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इन राज्यों में 'डबल इंजन' सरकारों के गठन से निःसंदेह विकास की गति दुगुनी होगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जारी भाजपा संकल्प पत्र झारखंड की रोटी, बेटी एवं माटी के लिए पार्टी की दृष्टि, प्रतिबद्धता एवं समर्पण को दर्शाता है। पिछले पांच वर्षों में झामुमो-कांग्रेस-आरजेडी के कुशासन से झारखंड भ्रष्टाचार एवं विकास विरोधी नीतियों का पर्याय बन गया। इस कारण जनता के धन की खुली लूट तो हुई ही, साथ ही खनिज संपदा से समृद्ध राज्य की संभावनाओं पर कड़ा कुठाराघात हुआ। जहां गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, युवा एवं महिला के हित कुचले गए, वहां भ्रष्टाचारियों को इनके हिस्से को लूटने की पूरी छूट मिली। भाजपा संकल्प पत्र में ऐसी कई अभिनव योजनाएं हैं जिनसे महिलाओं, युवाओं, किसानों, वंचितों एवं पीड़ितों को तुरंत राहत तो मिलेगी ही, साथ ही ऐसी दूरगामी योजनाएं हैं जिनसे 'विकसित झारखंड' का मार्ग प्रशस्त होगा। अवैध घुसपैठ जो आदिवासी समाज एवं संस्कृति के लिए एक खतरा बन गया है, उससे मुक्ति के लिए संकल्प पत्र स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है तथा घुसपैठियों द्वारा झारखंड की बेटियों की लूटी गई जमीन को वापस दिलाने के लिए कृतसंकल्पित है। साथ ही, राज्य के सांस्कृतिक केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कर इसको इको-पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए संकल्पित हैं।

> **पिछले दस वर्षों में भाजपा परफॉर्मेंस एवं विकास की राजनीति को देश में स्थापित करने में सफल हुई है। साथ ही, भाजपा आज भ्रष्टाचार, कुशासन, भाई-भतीजावाद, तुष्टीकरण एवं वोटबैंक की राजनीति के विरुद्ध एक सशक्त गारंटी बनकर उभरी है**

महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एक सुदृढ़, समृद्ध एवं सुरक्षित राज्य के निर्माण के लिए 'भाजपा संकल्प पत्र' जारी किया। संकल्प पत्र में लाडली बहन योजना एवं वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाने से लेकर किसानों की कर्ज माफी, किसान सम्मान निधि की बढ़ी राशि तथा मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए मूल्य स्थिर निधि स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जहां महायुति सरकार महाराष्ट्र को 2028 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कृतसंकल्पित है, वहीं, छात्रों, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अनेक योजनाओं के साथ बिजली बिल को 30 प्रतिशत कम करने की योजना की भी घोषणा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना, एयरोनॉटिक्स एवं अंतरिक्ष केंद्र, मैन्युफैक्चरिंग में महाराष्ट्र को अग्रणी राज्य बनाने तथा 4500 गांवों में सड़कें बनाने का लक्ष्य महाराष्ट्र को 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ करेंगे। किसान, महिला, युवा, गरीब, वरिष्ठ नागरिक से लेकर समाज के कमजोर, वंचित एवं पीड़ित वर्गों के लिए भाजपा संकल्प पत्र में कई योजनाएं हैं। जहां धर्मपरिवर्तन विरोधी कड़े कानून लाने का संकल्प है, वहीं महाराष्ट्र के जन-जन की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व यह संकल्प पत्र कर रहा है।

पिछले दस वर्षों में भाजपा परफॉर्मेंस एवं विकास की राजनीति को देश में स्थापित करने में सफल हुई है। साथ ही, भाजपा आज भ्रष्टाचार, कुशासन, भाई-भतीजावाद, तुष्टीकरण एवं वोटबैंक की राजनीति के विरुद्ध एक सशक्त गारंटी बनकर उभरी है। 'अमृतकाल' में 'पंच प्रण' के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान से देश को एक नई दिशा मिली है। परिणामस्वरूप आज जन-जन में एक नई ऊर्जा एवं चेतना का संचार हुआ है तथा देश 'विकसित भारत' के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संकल्पित हुआ है। भाजपा के चुनाव प्रचार को आज जनता का भरपूर प्यार एवं आशीर्वाद मिल रहा है और इसी कारण यह पूरे देश की पहली पसंद बनकर उभरी है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

झारखंड विधानसभा चुनाव : गढ़वा एवं चाईबासा में जनसभाएं

रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है भाजपा : नरेन्द्र मोदी

दो चरणों में आयोजित होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 13 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुका है। इसमें 64.86 प्रतिशत मतदान हुआ था। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। भाजपा नेतागण लगातार रोड शो एवं जनसभाओं के माध्यम से चुनाव-प्रचार में जुटे हुए हैं। हम यहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की जनसभाओं के संक्षिप्त समाचार प्रकाशित कर रहे हैं:

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 नवंबर, 2024 को झारखंड में दो जनसभाओं को संबोधित किया। गढ़वा में लोगों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्ष देश और झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में बेहतर सुविधाओं और यहां के किसानों और उद्योगों को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश की है। राज्य में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद यहां भी विकास डबल तेजी से होने वाला है।

श्री मोदी ने कहा कि भाजपा, झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। भाजपा का संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि माताओं-बहनों-बेटियों के लिए अनेक संकल्प लिए गए हैं, जिससे उनका जीवन आसान होने वाला है।

उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, वहीं दूसरी तरफ झामुमो-कांग्रेस-राजद सरकार के झूठे वायदे हैं। इन दलों की चुनावी घोषणाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा की नेक-नीयत कहां से लाएंगे?

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में 16 लाख गरीबों के घर बनाए हैं। जिनके पास पक्के घर नहीं थे, ऐसे एससी, एसटी और गरीब परिवारों का घर का सपना पूरा हुआ है। अपनी जनसभा को लेकर उन्होंने कहा कि गढ़वा के लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाने कि लिए भी नसीब चाहिए। ये नसीब मोदी

को मिला है। वहीं झारखंड के नौजवानों के टैलेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन झामुमो-कांग्रेस-राजद ने झारखंड के युवाओं के साथ भी धोखा ही किया। बीते 5 वर्षों में झारखंड के नौजवानों के साथ क्या-क्या हुआ, ये भी आपने देखा है। वोट के लिए उनसे झूठा वादा किया गया, लेकिन अब ऐसे लोगों को सजा देने का वक्त है।

श्री मोदी ने कहा कि झारखंड में भर्तियों में धांधली, पेपर लीक उद्योग बन चुके हैं, लेकिन अब भाजपा ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा सरकार बनने के बाद 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा, उन्होंने युवाओं को युवा साथी भत्ता देने और पेपर लीक माफिया पर भी लगाम लगाने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि किसानों का हित और उनकी आय बढ़ाना, भाजपा की प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड भाजपा ने धान की सरकारी खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने का भी फैसला लिया है। इसके साथ ही आदिवासी परिवारों की आजीविका बढ़ाने के लिए भी अनेक अच्छी घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा, "मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन्हें पूरा करने के लिए भाजपा-एनडीए सरकार पूरी ताकत से काम करेगी। ये मोदी की आपको गारंटी है।"

उन्होंने कहा कि आजकल अफवाहें फैलाने का एक बड़ा उद्योग चल पड़ा है। कुछ लोग भांति-भांति की दुकानें खोलकर बैठे हैं और वो अफवाह फैलाने का माल बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही झूठ और जनता से धोखा, कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है। लेकिन कांग्रेस और उसके साथी जहां-जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्य को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। अब तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भरोसा नहीं करना है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने झामुमो-कांग्रेस-राजद पर निशाना साधा और कहा कि इससे सबसे ज्यादा परेशान राज्य के गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी हुए हैं।

प्रधानमंत्री बालू माफिया को लेकर भी झारखंड की सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि यहां की सरकार माफिया की गुलाम बनी हुई है। जनता पलायन के लिए मजबूर है और ये लोग सरकारी ठेकों में बंदरबांट करने में व्यस्त हैं। यहां हर काम-धंधा बंद होता जा रहा है, लेकिन ट्रांस्फर-पोस्टिंग का धंधा खूब फल-फूल रहा है। इसलिए आपको याद रखना है कि झामुमो-कांग्रेस-राजद ने जो माफिया तंत्र बनाया है, भाजपा-एनडीए को दिया आपका हर वोट उस पर चोट करेगा।

झामुमो-कांग्रेस-राजद के तुष्टीकरण का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये तीनों दल राज्य का सामाजिक ताना-बाना तोड़ने पर आमादा हैं। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक हैं, जो आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा, दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है।

गांधी परिवार हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रहा है

झारखंड के चाईबासा में अपनी दूसरी रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भाजपा के लिए अपने आदिवासी भाई-बहनों की आकांक्षा, उनका स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि रहा है। उन्होंने कहा कि बीते दशक में आदिवासी समाज के योगदान को देश-दुनिया के सामने रखने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। 15 नवंबर से धरती आबा की डेढ़ सौवीं जन्मजयंती के उत्सव शुरु होने वाले हैं, आने वाले 2 सालों तक ये उत्सव देशभर में चलेगा।

उन्होंने कांग्रेस और राजद को सबसे बड़ा आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस के दामन पर आदिवासियों के खून के छींटे हैं, लेकिन आज झामुमो उसी के कंधे के सहारे सरकार चला रही है। झामुमो ने सत्ता के लालच में उन्हीं को गले लगा लिया। झारखंड राज्य के लिए अपना बलिदान देने वालों का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता।

संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भाजपा-राजग की हर योजना के केंद्र में माताएं-बहनें ही रहती हैं। इसलिए उन्हें खुशी है कि झारखंड भाजपा ने महिलाओं को सशक्त करने वाला संकल्प पत्र जारी किया है। उन्होंने गोगो दीदी योजना का भी जिक्र किया और कहा कि सशक्त नारी, विकसित भारत और विकसित झारखंड का मार्ग सशक्त करेगी।

आरक्षण का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि गांधी परिवार हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रहा है। अब एक बार फिर इन लोगों ने खुला ऐलान कर दिया है कि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर देंगे। आदिवासियों से आरक्षण का अधिकार छीनकर ये लोग उसे अपने वोटबैंक को दे रहे हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश से भी आपको सावधान रहना है। ■

मुख्य बातें

- **भाजपा; झारखंड की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है**
- **जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी घोर परिवारवादी दल हैं; हर हाल में सत्ता पर काबिज रहना ही इनका एकमात्र मकसद**
- **जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचाया**
- **भाजपा के लिए, आदिवासी भाई-बहनों की आकांक्षा और उनका स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि**
- **कांग्रेस और उसके साथी दलों ने लंबे समय तक आदिवासी समाज को गरीबी और अभावों में रखा**
- **भारत को विकसित बनाने के लिए आदिवासी समाज का विकास की मुख्यधारा से जुड़ना ज़रूरी**

एक मंत्र याद रखना है हम एक हैं, तो सेफ हैं : नरेन्द्र मोदी

महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। चुनावों के परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। भाजपा नेतागण इस चुनाव में मतदाताओं से 'विकसित महाराष्ट्र- विकसित भारत' के लिए मतदान करने का आग्रह कर रहे हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवंबर, 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित दो जनसभाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता एक ओर महायुति का जन-विकास का घोषणापत्र तो दूसरी ओर महा-अघाड़ी का घोटालापत्र साफ-साफ देख रही है। ये फिर से घोटाले न कर पाएं, इसलिए जनता-जनार्दन को अघाड़ी वालों को सरकार से दूर रखना है। उन्होंने कहा कि परजीवी कांग्रेस अब केवल बैसाखियों पर ही जिंदा है। राजनीति में खुद को बचाने के लिए कांग्रेस के पास अब यही हथियार बचा है— एससी-एसटी-ओबीसी समाज की एकता तोड़ो और सत्ता छीनो! कांग्रेस ने नेहरू जी के समय ओबीसी को अलग-अलग जातियों में बांटकर रखा है। उसका मकसद अब भी समाज को जातियों में बांटना और आपस में लड़ाना ही है। इसीलिए, आपको मेरा एक मंत्र याद रखना है— हम एक हैं, तो सेफ हैं।

पवित्र नगरी नासिक की जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि आज हमारा महाराष्ट्र हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और देश नित नए-नए रिकॉर्ड बना रहा है, क्योंकि अब देश में गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। कांग्रेस और उसके साथियों ने इतने दशकों तक सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन हम 10 वर्षों में ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर ले आए। ये इसलिए संभव हो पाया, क्योंकि मोदी की नीयत सही है और वह आपका सेवक बनकर काम करता है। महाराष्ट्र में गरीबों के कल्याण के लिए आगे भी लगातार काम होते रहें, इसलिए यहां फिर से महायुति की सरकार जरूरी है। मैं मेरे किसान साथियों को बताना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनेगी, तो उनकी मदद की राशि 12 हजार बढ़कर 15 हजार रुपए हो जाएगी।

प्रगति पथ पर बढ़ रहे भारत की बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए महाराष्ट्र का तेजी से आगे बढ़ना जरूरी है। महाराष्ट्र बढ़ेगा, तभी भारत विकसित बनेगा। महाराष्ट्र किस स्पीड से आगे बढ़ सकता है, पिछले ढाई वर्षों में महायुति सरकार ने यह दिखाया है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में महाराष्ट्र बहुत आगे हैं। यहां बन रहे हाइवेज और एक्सप्रेसवेज से राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा 2026 के कुंभ में भी मिलेगा। महाराष्ट्र में अटल सेतु हो या वाढवण पोर्ट का निर्माण हो, कांग्रेस अड़ंगा लगाने आ जाती है। उसने मेट्रो परियोजनाओं से लेकर समृद्धि महामार्ग के काम को रोकने का भरपूर प्रयास किया था।

डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारा नासिक डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। नासिक में लड़ाकू विमान और सुरक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं। यह नासिक के हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ ये महा-अघाड़ी वाले देश को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इन लोगों ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में देश को पीछे करने के लिए क्या कुछ नहीं किया! इन्होंने एचएएल को लेकर तरह-तरह के विवाद खड़े करने की कोशिश

की, लेकिन आज वही एचएएल रिकॉर्ड मुनाफे वाली कंपनी बनकर उभरी है। जब नीतियां स्पष्ट होती हैं, नीयत साफ होती है तो अच्छे परिणाम आते ही हैं।

कांग्रेस की नीतियों पर प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसको न बाबासाहेब के संविधान की परवाह है, न ही कोर्ट की। ये सिर्फ दिखावे के लिए जेब में कोरे पन्ने वाले संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। जब संविधान की रक्षा की बात आती है, तो ये उल्टा ही काम करते हैं। कांग्रेस ने 75 साल तक जम्मू-कश्मीर में संविधान को लागू नहीं होने दिया। भाजपा-एनडीए ने 'आर्टिकल-370' को हटाया और 'एक देश एक संविधान' लागू किया। यह मेरी बाबासाहेब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। जब भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर में लागू हुआ तो पूरा देश खुशी से झूम उठा था, लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। हाल ही में जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस और इसके साथियों ने 370 फिर से लागू करने के लिए हंगामा किया। ये लोग चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर से बाबासाहेब का संविधान फिर हट जाए।

श्री मोदी ने कांग्रेस को झूठ की दुकान बताते हुए कहा कि इन दिनों कांग्रेस और उसके चेलों ने ऐसी ही दुकान महाराष्ट्र में लगाई है। कांग्रेस ने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में भी यही दुकान सजाई थी। वहां क्या हाल हुआ? चुनाव खत्म होते ही दुकान का शटर गिरा दिया। वादे पूरे करना तो दूर कांग्रेस शासित राज्यों का यह हाल है कि वहां प्रशासन चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। राज्य के कर्मचारियों को तनख्वाह देने और अपनी जेबें भरने के लिए जनता पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। जनता भी इनकी असलियत जान चुकी है। इसलिए इनकी ये धोखेबाजी महाराष्ट्र में चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मराठी संस्कृति और इतिहास में हमारी आस्था है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की बात की, उनके सम्मान को आगे बढ़ाया। भाजपा गर्व से कहती है कि वीर सावरकर हमारे प्रेरणास्रोत हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और महा-अघाड़ी के लोग घूम-घूमकर वीर सावरकर को गाली देते हैं। मैं कांग्रेस और महा-अघाड़ी को चुनौती देता हूं कि ये लोग कांग्रेस के युवराज से वीर सावरकर के तप, त्याग और बलिदान की प्रशंसा करवाकर दिखाएं।

मुख्य बातें

- **महिला सशक्तीकरण की दिशा में माझी लाडकी बहिण योजना जैसे कदम कांग्रेस और उसके गठबंधन को बर्दाश्त नहीं हो रहे**
- **कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती**
- **आदिवासी समाज, भाजपा के 'सबका साथ-सबका विकास' संकल्प का अहम हिस्सा है**
- **कांग्रेस और इसके साथियों को न बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान की परवाह है, न ही देश की भावना की**
- **कांग्रेस और अघाड़ी वाले लोग देश को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते**
- **परजीवी बन चुकी कांग्रेस, अब ज्यादातर राज्यों में दूसरी पार्टियों की बैसाखियों पर ही जिंदा है**

महिलाओं का सशक्त होना बेहद जरूरी

महाराष्ट्र के धुले में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 'विकसित महाराष्ट्र-विकसित भारत' के लिए हमारी बहनों-बेटियों का जीवन आसान और सशक्त बनाना बेहद जरूरी है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो पूरा समाज तेजी से प्रगति करता है। इसीलिए पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर बड़े फैसले लिए हैं। हमने महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में काम के अवसर दिए हैं। नारीशक्ति वंदन अधिनियम के जरिए विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को आरक्षण का अधिकार दिया। आज हमारी योजनाएं महिला सशक्तीकरण का पर्याय बन गई हैं। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार भी हमारे विजन को आगे बढ़ा रही है। आप जानते हैं कि महायुति सरकार की माझी लाडकी बहिण योजना की कितनी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस और उसके साथी इस योजना को बंद करवाने की साजिश रच रहे हैं। वे इस योजना के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए। इसलिए महाराष्ट्र की हर महिला को इन अघाड़ी वालों से सतर्क रहना है।

श्री मोदी ने अपने संबोधन के अंत में आदिवासी भाई-बहनों के कल्याण का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा 'सबका साथ, सबका विकास' की नीयत से काम किया है। इस संकल्प का प्रमुख हिस्सा हमारा आदिवासी समाज भी है। ये वो समाज है, जिनका देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों ने कभी आदिवासी गौरव और स्वाभिमान पर ध्यान नहीं दिया। जब अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई, तब अलग आदिवासी मंत्रालय बना। तब पहली बार आदिवासियों के हितों और उनकी अपेक्षाओं को महत्व मिला। हमारी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की है। इस बार 15 नवंबर से हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म-जयंती को पूरे साल मनाएंगे। ■

झारखंड के विकास, अस्मिता के बचाव और उज्ज्वल भविष्य का रास्ता केवल कमल की सरकार है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 9 नवंबर, 2024 को झारखंड के विश्रामपुर एवं रामगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार द्वारा झारखंड और आदिवासियों के लिए किए गए विकास और कल्याण कार्यों को रेखांकित किया और हेमंत सोरेन की भ्रष्ट सरकार पर जमकर निशाना साधा।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। इस बार उनकी 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव वर्ष मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के गांव जाकर उस माटी को नमन किया और जनजाति समाज को देश की मुख्यधारा से जोड़ा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर देश को आदिवासी समुदाय से पहला राष्ट्रपति दिया। मोदी सरकार ने जनजातीय लोगों के विकास के बजट को 3 गुना बढ़ाया। एकलव्य मॉडल स्कूल के बजट को 21 गुना बढ़ाया गया। पहले केवल 10 वन उत्पादों पर एमएसपी प्रदान की जाती थी, आज 90 वन उत्पादों पर एमएसपी मिल रही है। केंद्र सरकार ने देश में 11 करोड़ से अधिक इज्जतघरों का निर्माण किया, जिनमें से 1.5 करोड़ आदिवासी समाज के लोगों के लिए बनाए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है, जो आदिवासी समाज की तस्वीर और तकदीर को बदलकर रख देगा।

श्री नड्डा ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार घोटालेबाजों की सरकार है जिसने जनता के साथ सिर्फ छल किया। इन्होंने बेकारी भत्ता, महिलाओं को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी देने का वादा किया, मगर एक भी पूरा नहीं किया। कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम छलावे और धोखा देने के साथ चोरों का साथ देने वाली सरकार है। इनके अफसरों और सीए के घरों से 25 से 30 करोड़ रुपये नकदी बरामद किए गए। हेमंत सोरेन के साथ साथ उनके अफसरों को भी जेल जाना पड़ा और हेमंत सोरेन अब भी बेल पर बाहर हैं, दोषमुक्त नहीं हुए हैं। झारखंड में कांग्रेस के सांसद के घर से 322 करोड़ रुपए मिले, जिसे गिनने में हफ्ते भर का समय लगा। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री के पीए के घर से 22 करोड़ रुपए बरामद हुए। यह सभी पैसे झारखंड की जनता के हैं। इन चोर और बेईमानों की बारात को घर बैठाने की आवश्यकता है। भाजपा सरकार के समय प्रदेश में नक्सलियों पर नकेल कसने का काम किया गया था, मगर हेमंत सोरेन की सरकार में नक्सलियों के हौंसले बढ़ गए। झारखंड के विकास, अस्मिता के बचाव और उज्ज्वल भविष्य का रास्ता केवल कमल की सरकार है। श्री नड्डा ने भाजपा और एनडीए को भारी मतों से जिताकर, झारखंड में 'डबल इंजन' सरकार बनाने की अपील की।

मुख्य बातें

- झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की पुकार, इस बार भाजपा-एनडीए की सरकार
- हेमंत सोरेन ने जनता से जितने भी वादे किए, वो सब झूठे निकले और भ्रष्टाचार के मामले में उनके साथ-साथ उनके अफसरों को भी जेल की हवा खानी पड़ी
- भाजपा की सरकार बनने के बाद सभी घुसपैठियों को बाहर निकाल जाएगा। ये घुसपैठिए झारखंड की बेटियों के साथ विवाह कर उनकी जमीने हड़पते हैं, भाजपा सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाएगी, जिससे इनकी संतानों को कोई भी आदिवासी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकेंगे
- भाजपा सरकार के समय प्रदेश में नक्सलियों पर नकेल कसा था, मगर हेमंत सोरेन की सरकार में नक्सलियों के हौंसले बढ़ गए
- मोदी सरकार ने जनजातीय विकास बजट को 3 गुना और एकलव्य मॉडल स्कूल का बजट 21 गुना बढ़ाया। पहले केवल 10 वन उत्पादों पर एमएसपी प्रदान की जाती थी, आज 90 वन उत्पादों पर एमएसपी मिल रही है
- झारखंड में भाजपा सरकार बनने के बाद गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए माताओं-बहनों के खातों में भेज जाएंगे ■

'डॉक्टर संवाद', रांची (झारखंड)

'झारखंड को भाजपा के डबल इंजन की आवश्यकता है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 9 नवंबर, 2024 को रांची में डॉक्टरों से संवाद करते हुए मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास और कल्याण कार्यों को रेखांकित किया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर केंद्रीय मंत्री श्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद श्री दीपक प्रकाश, डॉ. राघव चरण सहित पार्टी के अन्य नेता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

श्री नड्डा द्वारा दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु

- जब हम डॉक्टर समुदाय से मिलते हैं, तो चर्चा भले ही छोटी हो, लेकिन उसका प्रभाव दूरगामी होता है।
- न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में, बल्कि पूरे देश में चौतरफा विकास हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हर वर्ग और क्षेत्र ने विकास का अनुभव किया है।
- 60 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार चुनकर आया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
- पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 90 लाख करोड़ रुपये का भारी निवेश किया गया है। इसके परिणामस्वरूप चार-लेन और छह-लेन राजमार्ग, औद्योगिक गलियारे और ग्रीनफील्ड परियोजनाएं बनाई गई हैं, जो भारत के विकास में महत्वपूर्ण छलांग के प्रमाण हैं।
- झारखंड में 2,556 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। अंडरपास, ओवरब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड सड़कों के विकास ने राज्य की छवि बदल दी है।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लोगों यानी 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है। 29 अक्टूबर, 2024 को मोदी सरकार ने 70 साल से अधिक उम्र के देश के हर नागरिक को आजीवन 5 लाख रुपये प्रति वर्ष मुफ्त इलाज की मंजूरी दी। भाजपा झारखंड में हर साल 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगी।
- विश्व बैंक का कहना है, "वैश्विक मंदी के दौरान भी भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।" कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा गई, जापान और यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, लेकिन भारत कोरोना महामारी के सामने मजबूती से खड़ा रहा और उसे हराकर बाहर आया।
- भारत में ट्यूबरक्लोसिस की दवा आने में 25 साल लग गए, टिटनेस की दवा को आने में 28 साल लगे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में जनवरी, 2020 में देश का पहला कोरोना केस आने के 9 महीने के भीतर कोरोना की 2-2 वैक्सीन बनाकर देश की 140 करोड़ जनता को डबल डोज देकर कोरोना महामारी से सुरक्षित किया गया।
- अमेरिका में कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट कागज पर मिलता है, लेकिन भारत में कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट मोबाइल फोन पर प्राप्त हो जाता है। देश में यह बदलाव आया है।
- वर्ष 2014 में केवल 6 एम्स थे लेकिन आज देश भर में 22 एम्स हैं, जिसमें एक झारखंड का देवघर एम्स भी शामिल है। आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि झारखंड के किसी रोगी को दिल्ली न जाना पड़े।
- पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे आज 766 मेडिकल कॉलेज हैं। मेडिकल सीटों में 125% कि बढ़ोतरी हुई है और इस वर्ष 10000 मेडिकल सीट बढ़ाई गई हैं। आगे 75000 मेडिकल सीटें बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है।
- एक समय था, जब ब्रेन ड्रेन की चर्चा होती थी। आज हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ भारत की ही नहीं, दुनिया की चिंता कर रहे हैं। इसलिए हम डॉक्टर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, साथ ही हम पैरामेडिक को भी उस स्तर पर ले जाएंगे, ताकि देश के साथ हम दुनिया की भी सेवा कर सकें।
- प्रति लाख जनसंख्या पर टीबी के मामले 237 से घटकर 199 रह गए हैं। टीबी को खत्म करने पर फोकस है और 2027 तक इसे खत्म कर दिया जाएगा। जन आरोग्य केंद्रों के माध्यम से गरीबों को दवाइयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
- झारखंड में पांच नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं तथा 10 और मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है।
- झारखंड में आईएमआर 34 से घटकर 25 हो गया है और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 44 से घटकर 27 हो गई है। इसलिए झारखंड में भी स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण बदलाव आया है।
- मोदी सरकार रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिव, प्रो ऐक्टिव और प्रो पीपल गवर्मेंट है। झारखंड को भाजपा के डबल इंजन की आवश्यकता है। ■

झारखंड में झामुमो-कांग्रेस-राजद ने जनता को झूठे आश्वासन देकर गुमराह किया

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 9 नवंबर, 2024 को झारखंड के खूंटी और चतरा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए गठबंधन द्वारा आदिवासी कल्याण के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया और झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर झामुमो व कांग्रेस की आलोचना की। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद श्री करिया मुंडा, नागालैंड से राज्यसभा सांसद श्रीमती एस फांगनोन कोन्याक सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे।

श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार बन जायेगी, तो हम जातिगत जनगणना करायेंगे और भारत में कुल कितनी जातियां है हम इसका पता लगायेंगे। मैं कांग्रेस के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि साल 2011 में एक सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना हुई थी और जिस पर करीब 46 लाख जातियां-उपजातियां और गोत्र निकल कर आये थे। यह संख्या इतनी बड़ी थी कि उस समय जिन लोगों ने यह रिपोर्ट तैयार की थी, उन लोगों ने इस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया था। समाज कल्याण मंत्रालय के अनुसार अनुसूचित जातियां लगभग 1200 से अधिक थीं और अनुसूचित जनजातियां लगभग 750 से अधिक थीं और ओबीसी जातियां लगभग ढाई हजार के आस-पास थी। यह जात का पिटारा खोल कर कांग्रेस किसका भला करना चाहती है। कांग्रेस ने 50 वर्षों तक इस देश में हुकूमत की है तो पहले क्यों नहीं चिंता की कि जातिगत जनगणना करानी चाहिये और जाति के आधार पर लोगों को आरक्षण की सुविधा देनी चाहिये।

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि यदि कांग्रेस को लगता है कि भाजपा ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है, तो वे साहस के साथ आगे आएं और जनता की अदालत में अपना पक्ष रखें। भाजपा उनके हर आरोप का जवाब देगी। हम पूरी निष्ठा से यह कह सकते हैं कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद ने भारत की जनता से जो भी वादे किए, उन्हें कभी पूरा नहीं किया। उन्होंने केवल जनता को झूठे आश्वासन देकर गुमराह किया। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। भाजपा जो कहती है, उसे पूरा करती है।

श्री सिंह ने कहा कि झारखंड में 5 वर्षों से झामुमो-कांग्रेस और राजद की सरकार है, 5 वर्षों में इन्होंने झारखंड में लूट का माहौल बना दिया है। भ्रष्टाचार के मामले में स्वयं झारखंड के मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं। लंबे समय से देश के कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री पर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। ■

प्रधानमंत्री मोदीजी ने लालकृष्ण आडवाणी जी के 97वें जन्मदिन पर उनसे भेंट की, भारतीय राजनीति में उनके योगदान की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व उप-प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री लालकृष्ण आडवाणी से 8 नवंबर, 2024 को उनके 97वें जन्मदिन के अवसर पर भेंट की और उन्हें इस अवसर पर शुभकामनाएं दीं। इस दौरान श्री मोदी ने भारतीय राजनीति में उनके योगदान की सराहना की।

इससे पहले 'एक्स' पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, "लालकृष्ण आडवाणी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष और भी खास है क्योंकि इसी वर्ष आडवाणी जी को राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वह भारत के सबसे प्रशंसित राजनेताओं में से एक हैं, उन्होंने भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं को समर्पित किया है। उनकी बुद्धिमत्ता एवं समृद्ध अंतर्दृष्टि के लिए उन्हें हमेशा सम्मानित किया जाता रहेगा। मुझे कई वर्षों तक उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं। मैं उनके लंबे एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।"

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा भी इस अवसर पर श्री आडवाणी के निवास पर गए और उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री नड्डा ने 'एक्स' पर लिखा, "भाजपा के वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व उप-प्रधानमंत्री, भारत रत्न आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आदरणीय श्री आडवाणी जी ने अपने समर्पण और कठिन परिश्रम से भाजपा को सींचकर देशभर में इसे विस्तार देने तथा असंख्य कार्यकर्ताओं को गढ़ने में महनीय भूमिका निभाई है। संगठन के विस्तार एवं राष्ट्रसेवा के आपके महान विचार और कार्य करोड़ों कार्यकर्ताओं के पाथेय हैं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं।"

कमल संदेश परिवार भी पूर्व उप-प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता है तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्रार्थना करता है। ■

शिराला, सतारा, सांगली एवं कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

डबल इंजन की भाजपा सरकार महाराष्ट्र को सबसे बेहतर राज्य बनाने का कार्य करेगी: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 8 नवंबर, 2024 को महाराष्ट्र के शिराला, सतारा, सांगली और कोल्हापुर में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और महाराष्ट्र की जनता से भारी बहुमत से महायुति सरकार बनाने की अपील की। श्री शाह ने महाविकास अघाड़ी को विकास विरोधी बताते हुए राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्र विरोधी रुख को लेकर उसकी जमकर आलोचना की।

श्री शाह ने कहा कि 20 तारीख को समग्र महाराष्ट्र में मतदान होना है जिसमें महाराष्ट्र की जनता को निर्णायक भूमिका निभानी है। केन्द्र में तो श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार है और यदि महाराष्ट्र की जनता यहां भी भाजपा की सरकार बना दें तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार महाराष्ट्र को देश का सबसे बेहतर राज्य बनाने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्रीजी ने एक ऐसे भारत को बनाने का लक्ष्य रखा है, जो दुनिया के हर क्षेत्र में सर्वप्रथम हो और ऐसा देश केवल एनडीए के नेतृत्व में ही संभव है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस, एनसीपी और नकली शिव सेना वाले कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 नहीं हटानी चाहिए। जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया है कि धारा 370 को फिर से वापस लेकर आएंगे, ये लोग जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते हैं। अघाड़ी वालों की चार पुश्तें भी बदल जाएंगी, तब भी जम्मू-कश्मीर में धारा 370 वापस नहीं आएगी।

श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में कुछ नया सीखा है, क्योंकि उनके एनजीओ सहयोगियों ने उन्हें संविधान की एक प्रति सौंपी। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान संविधान की एक प्रति वितरित की गई, लेकिन कवर पेज तो सही था, लेकिन अंदर के सभी पेज खाली थे। राहुल गांधी ने देश के संविधान और डॉ. बीआर अंबेडकर दोनों का अपमान किया है, देश को धोखा दिया है। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि जिस संविधान की उन्होंने शपथ ली है, वह असली है या नकली। हाल ही में राहुल गांधी विदेश गए और दावा किया कि भारत में आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि, मोदी सरकार में कोई भी संविधान से छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण अपरिवर्तित रहेगा। ■

छतरपुर, हजारीबाग एवं पोटका (झारखंड)

'हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असुरक्षा और घुसपैठ का माध्यम बनाकर रख दिया'

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 9 नवंबर, 2024 को झारखंड के छतरपुर, हजारीबाग और पोटका की जनसभाओं को संबोधित करते हुए बीते 10 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा झारखंड के लिए किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। श्री शाह ने कहा कि 2014 में डबल इंजन के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड को विकास के पटरी पर लाने का काम किया था, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असुरक्षा और घुसपैठ का माध्यम बनाकर रख दिया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री रवींद्र राय, सांसद श्री विष्णु दयाल राम सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

श्री शाह ने कहा कि झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है और झामुमो-कांग्रेस-आरजेडी सरकार पूरे देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। झारखंड की जनता ने कभी 300 करोड़ रुपये एक साथ नहीं देखे होंगे, लेकिन कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपये पकड़े गए जिन्हें गिनने के लिए 27 मशीनें लगानी पड़ीं। झारखंड के मंत्री आलमगीर के पीए के घर से 30 करोड़ रुपये पकड़े गए, लेकिन हेमंत सोरेन और झामुमो सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। यह जो करोड़ों रुपये पकड़े गए हैं यह झारखंड के युवाओं के हैं, जो कांग्रेस खा गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शासन में भ्रष्टाचार करने वालों की जगह जेल में है। झामुमो और इनके साथियों ने झारखंड के गरीबों और युवाओं के पैसों से अपना घर भरा है।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, यह जब भी शासन में आई है, इन्होंने हमेशा पिछड़े वर्ग का विरोध किया। 1950 में काका कालेलकर कमीशन बनी, लेकिन इसकी रिपोर्ट को कांग्रेस ने सामने नहीं आने दी, इसी तरह पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए मण्डल कमीशन बनाया गया, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मण्डल कमीशन का विरोध किया और केन्द्रीय संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने में वर्षों का समय लग गए। वर्ष 2014 में झारखंड और देश की जनता ने भाजपा सरकार बनाई, तो प्रधानमंत्रीजी ने केन्द्र की सभी परीक्षाओं और नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का कार्य किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और उसे संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किया। ■

भाजपा अन्य पार्टियों की तरह केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि संकल्प लेकर उन्हें पूर्ण करती है : अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 3 नवंबर, 2024 को रांची में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन किया और झारखंड में भाजपा-नीत सरकार बनने पर झारखंड के विकास का रोडमैप जनता के सामने रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड के लिए किये गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए झामुमो, कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन पर अवैध घुसपैठ, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, आदिवासियों की सुरक्षा और झारखंड में डेमोग्राफी चेंज को लेकर जोरदार हमला बोला। कार्यक्रम में मंच पर झारखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा, पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. रवींद्र राय, केंद्रीय मंत्री श्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा सहित अन्य प्रदेश भाजपा के कई वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्री शाह ने कहा कि झारखंड का आगामी विधानसभा चुनाव केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं, बल्कि झारखंड के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की जनता को यह तय करना है कि उन्हें आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार चाहिए या प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के पथ पर चलने वाली भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड में घुसपैठ करवाकर रोटी, बेटी और माटी को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके, ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भाजपा सरकार चाहिए।

उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों की तरह केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि संकल्प लेकर उन्हें पूर्ण करती है। भाजपा देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है, 'जो कहती है, वो करती है।' भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों का इतिहास रहा है, जब-जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, उसने अपने सभी संकल्पों को पूरा किया।

संकल्प पत्र के मुख्य बिंदु

- गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए माताओं-बहनों के खातों में भेजेगी।
- माताओं-बहनों को 500 रुपए की कीमत पर गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा और दीपावली तथा रक्षा बंधन पर एक सिलेंडर निःशुल्क दिया जाएगा।
- झारखंड के युवाओं के लिए 5 वर्ष में 5 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे और करीब 3 लाख सरकारी पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्तियां की जाएंगी।
- परीक्षाओं का एक समेकिक केलेंडर जारी किया जाएगा और झारखंड के युवाओं को हर वर्ष 1 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- हर स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को 2 हजार रुपए प्रतिमाह का 'युवा साथी भत्ता' दिया जाएगा।
- झारखंड में हर गरीब को पक्के घर का वादा पूर्ण होगा और आवास योजना के 21 लाख मकानों को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।
- झारखंड के पेपरलीक माफियाओं की एसआईटी जांच कारवाई जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा।
- घुसपैठ को रोका जाएगा और घुसपैठियों द्वारा हड़पी हुई जमीनों को प्रदेश की बहन-बेटियों के नाम किया जाएगा।
- 1 रुपए में स्टाम्प ड्यूटी योजना शुरू की जाएगी।
- झारखंड की बेटियों को बीएड, नर्सिंग एवं अन्य व्यावसायिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा।
- आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए अनुदान और सहायता प्रदान की जाएगी।
- जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा, दुमका में सिद्धो कानो, पलामू में नीलांबर पीताम्बर, लोहरदगा में बोधऊ भगत, जगन्नाथपुर में

पोटोहो और गुमला में तेलंग खड़िया का भव्य स्मारक बनाया जाएगा।

- झारखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा और प्रदेश के आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा।
- मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 6 पोषण किट और 21 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जायेगी।
- युवाओं को बेहतर और उच्च शिक्षा के लिए 10 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा।
- आयुष्मान भारत और जीवनधार योजना की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा और 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले सदस्य के साथ यह राशि 15 लाख रुपये की जाएगी।
- सीएचसी, पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में 25 हजार नए बेड तैयार किए जाएंगे।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टालरन्स की नीति को अपनाते हुए एसआईटी जांच कारवाई जाएगी और भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजा जाएगा।
- अवैध खनन को बंद किया जाएगा और 181 सीएम हेल्पलाइन को पुनः शुरू किए जाएगा।
- प्रदेश में पंचायत के मुखियाओं का वेतन 5 हजार रुपए किया जाएगा और प्रदेश को गौ तस्करी से मुक्त किया जाएगा।
- किसानों के धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर से की जाएगी और 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा।
- पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण को किसी अन्य वर्ग के आरक्षण में कटौती किए बिना पूरा करने के नए तरीके खोजे जाएंगे।
- डायमंड एक्सप्रेस वे को पूरा किया जाएगा और पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 25 हजार किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी।
- सैट, नीट, आईआईटी, आईएएस, जेएएस और बैंकिंग की कोचिंग के लिए 20 हजार रुपए की स्कॉलरशिप और मुफ्त ऑनलाइन प्रीमियम पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाएगा।
- उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिए जाएगा, जिसके ब्याज का निर्वहन झारखंड की भाजपा सरकार करेगी।
- देश के हर शहर में झारखंड जोहार भवन स्थापित किया जाएगा।
- वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के पेंशन को 25 हजार रुपए तक बढ़ाया जाएगा।
- आदिवासी क्षेत्रों में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्रों को स्थापित किया जाएगा।
- सभी वन उत्पादनों की खरीदी की जाएगी।
- झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी, जो 5 लाख युवाओं को 1 लाख की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- आईआईटी को हब अंड स्पोक मॉडल के माध्यम से उन्नत किया जाएगा।
- प्रमुख देवी मंदिरों को जोड़ने वाले रास्तों को भगवती सर्किट के रूप में विकसित करेंगे।
- बाबा बैद्यनाथ और वसुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र को अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं के साथ लैस किए जाएगा।
- झारखंड को इको-टुरिज्म की राजधानी के तौर पर विकसित करेंगे।
- झारखंड राज्य में बोले जाने वाली मुण्डारी, कुरूक और शबरी सहित अन्य स्थानीय भाषाओं को राज्य की शिक्षण संस्थानों में लागू करेंगे। इसके साथ ही कुछ भाषाओं को झारखंड की अधिकृत भाषा के तौर पर भी घोषित करेंगे। 8वीं अनुसूची में उन भाषाओं को समाहित करने का कार्य करेंगे।
- आदिवासी भाषाओं को लेकर एक व्याकरण शब्दकोश तैयार करने के लिए एवं पूर्वी भाषाओं के लिए भी एक विद्वानों की समिति तैयार गठित करेंगे।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस चुनावी संकल्प पत्र में 5 प्रमुख वादे किये है, जिनके माध्यम से हम झारखंड का सर्वांगीण विकास करेंगे और इसके लिए भाजपा कटिबद्ध है। भाजपा झारखंड की जनता को विश्वास दिलाती है कि हम झारखंड को इस तरह विकसित करेंगे, जिससे किसी भी युवा को मजदूरी करने के लिए झारखंड से बाहर नहीं जाना होगा, युवाओं को यही राज्य के अंदर रोजगार उपलब्ध कराएंगे। राज्य में मौजूद खनिज संपदा का पूर्णतः उपयोग राज्य के विकास के लिए होगा। खनिज संपदा के आधार पर उद्योग लाएंगे और रोजगार देंगे। झारखंड की सरकार ने जिस तरह खनन कर खनिज संपदा को तार-तार किया है, हम उसको पुनः ठीक कर आदिवासी कल्याण का कार्य करेंगे। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े स्वप्न के साथ झारखंड की रचना की थी, वर्ष 2014 में डबल इंजन के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड को विकास के पटरी पर लाने का काम किया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपने 5 साल के शासन में राज्य को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असुरक्षा और घुसपैठ का माध्यम बनाकर रख दिया।

उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के सभी आदिवासी भाइयों आश्वासन देते हुए कहा कि यूसीसी से किसी भी आदिवासी भाई को डरने की जरूरत नहीं है, यूसीसी से हमारे किसी भी आदिवासी भाई का कोई भी अधिकार, कानून और कोई भी परंपरा बाधित नहीं होगी। राज्य में हमारी माताओं-बहनों के साथ हो रहे अत्याचार पर अंकुश लगाया जाएगा, घुसपैठ पर रोक लगाई जाएगी एवं हमारी बहनों को गुमराह कर उनसे दूसरी-तीसरी शादी कर जो जमीन छीनी गई है उसको पुनः हमारी बहनों को वापस दिया जाएगा।

श्री शाह ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बार पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गारंटी और विकास के लिए भाजपा के 'डबल इंजन' पर भरोसा जताते हुए राज्य में दो तिहाई बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। श्री शाह ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र केवल वादों का पुलिंदा मात्र नहीं है, बल्कि एक-एक वादा पत्थर की लकीर है जो पूरा होगा। ■

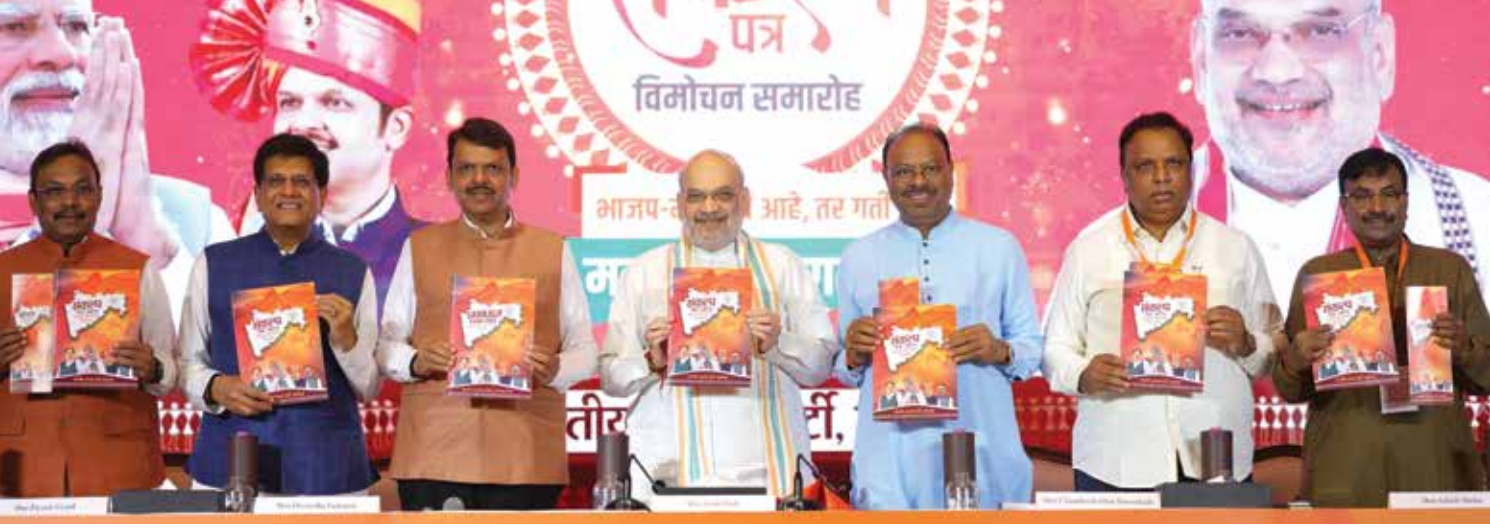

'महाराष्ट्र में जब भी भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की सरकार बनती है, तो यह आगे बढ़ता है'

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 10 नवंबर, 2024 को मुंबई में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 'संकल्प पत्र' का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में जब भी भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की सरकार बनती है, तो महाराष्ट्र आगे बढ़ता है और जब कांग्रेस नेतृत्व वाली अघाड़ी (एमवीए) की सरकार आती है, तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार बढ़ता है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर महाराष्ट्र भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री चंद्रकांत बावनकुले, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस, पूर्व राज्यसभा सांसद श्री विनय सहस्त्रबुद्धे, भाजपा के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार सहित अन्य प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

श्री शाह ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र पूरे महाराष्ट्र की जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र में भाजपा की महायुति सरकार ने किसानों का सम्मान, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने की योजनाओं के साथ विरासतों का पुनरुत्थान करने का संकल्प लिया है। हाल ही में सम्पन्न जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में आजादी के बाद पहली बार मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान के अनुरूप शपथ लिया है। यह बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति सच्ची और सर्वोत्तम श्रद्धांजलि मानी जा सकती है। धारा 370 के हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ लेकर सरकार बनी है और इस पर पूरे देश को नाज़ है। भाजपा ने अपने 'संकल्प पत्र' के माध्यम से महापुरुषों की परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासतों को संजोने और आगे बढ़ाने के संकल्प भी लिया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व की महा-अघाड़ी सरकारों द्वारा महाराष्ट्र में विकास के नाम पर अराजकता और भ्रष्टाचार राज दी गयी है। वहीं भाजपा की महायुति सरकार ने एक समृद्ध एवं सुरक्षित महाराष्ट्र बनाया है और भाजपा के संकल्प पत्र में विकसित महाराष्ट्र बनाने की योजना है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में महायुति का मुकाबला सत्ता के लालच में तुष्टीकरण, विचारधाराओं का अपमान एवं महाराष्ट्र की संस्कृति से छल करके केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली कांग्रेस की महा अघाड़ी गठबंधन से है। पिछले दोनों विधानसभा चुनावों में महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है और तीसरी बार भी आपको ये आशीर्वाद महायुति को देना है। वर्ष 2014 में महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा और महायुति को मैन्डेट दिया, 2019 में महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद भाजपा और महायुति के लिए ही था, लेकिन सत्ता के लालच में जनादेश को नकारा गया और आंकड़ों का बनावटी बंटवारा किया गया, लेकिन बनावटी चीजें ज्यादा देर तक चलती नहीं है जिस कारण बनावटी सरकार गिरी और पुनः असली महायुति की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि महायुति एकमुश्त और एकजुट होकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सिद्धांतों के आधार पर महाराष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ा रही है और दूसरी तरफ जो महाविकास अघाड़ी वाले सरकार बनाने का दावा कर रहे है और उनके खुद के पार्टी के अंदर आंतरिक विरोधाभास का चुनावी अभियान जारी है।

> **महाराष्ट्र में भाजपा की महायुति सरकार ने किसानों का सम्मान, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने की योजनाओं के साथ विरासतों का पुनरुत्थान करने का संकल्प लिया है**

श्री शाह ने कहा कि भाजपा की 'डबल इंजन' सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारे कार्य किए हैं। एनसीपी (शरद गुट) के प्रमुख शरद पवार 2004-14 तक यूपीए सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या कार्य किए, उन्हें इसका हिसाब देना चाहिए? यूपीए सरकार ने 10 साल में महाराष्ट्र को 1 लाख 91 हजार 384 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन मोदी सरकार ने बीते 10 वर्षों में महाराष्ट्र को 10 लाख 15 हजार 890 करोड़ रुपए प्रदान किए।

10 साल केंद्र और राज्य में यूपीए की सरकार होने के बावजूद महाराष्ट्र को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए, जबकि केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार होते हुए महाराष्ट्र को 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए प्रदान किए गए। यह महायुति और महाविकास अघाड़ी में अंतर को स्पष्ट करता है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने महाराष्ट्र के सिंचाई नेटवर्क को निलवड़े बांध, घोसीखुद, टेम्पू और जलयुक्त शिवहर जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्य की भूमि में सिंचाई क्षेत्र 30% तक बढ़ गया है। नदियों को जोड़ने के लिए नारपार्क, दबन गंगा, गोदावरी और वैटरणा का विकास करने का कार्य किया गया। महाराष्ट्र में 11 वंदे भारत ट्रेन लोगों को सेवा प्रदान कर रही है और 128 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। मुंबई, पुणे और नागपुर में मेट्रो का विस्तार किया गया। शिरडी और सिंहदुर्ग में नए हवाई अड्डे और टर्मिनल बनाए गए। 13 हजार करोड़ की लागत से बांद्रा-वर्ली से सी-लिंक जोड़ने वाले मुंबई कॉस्टल रोड का निर्माण किया गया। वाशीपुर का विस्तारीकरण किया गया और मेट्रो निर्माण फेज 1 का निर्माण समाप्त हुआ। अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण किया गया और 76 हजार करोड़ रुपए की लागत से वाधवान बंगरगाह के निर्माण का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा क्षमता वाला बंदरगाह होगा।

संकल्प पत्र के मुख्य बिंदु

- लाडली बहन योजना एवं वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की जाएगी।
- किसानों के ऋण माफी सहित उन्हें मिलने वाले किसान सम्मान निधि को 12 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 15 हज़ार रुपए सालाना किया जाएगा।
- मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से महंगाई को काबू किया जाएगा।
- 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10 हज़ार रुपए का मानदेय दिया जाएगा।
- 45 हज़ार गांव में सड़क बनाई जाएगी।
- आशा वर्करों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा किया जाएगा और सभी का मासिक वेतन भी 15 हजार रुपए तक बढ़ाया जाएगा।
- वर्ष 2028 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य महायुति सरकार करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य वाले भारत के अर्थतंत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान आने वाले समय में महाराष्ट्र करेगा।
- मेक इन महाराष्ट्र नीति के तहत प्रमुख उत्पादन वाले राज्य के तौर पर महाराष्ट्र को विकसित करेंगे।
- महाराष्ट्र में देश का पहला एआई (AI) विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
- नागपुर, पुणे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर एवं नासिक में वैमानिकी और अंतरिक्ष केंद्र बनाए जाएंगे।
- किसानों की आय बढ़ाने के लिए एसजीसटी के ऊपर छूट सहित सब्सिडी के रूप में पुनः किसानों को भुगतान की गई एसजीसटी लौटाई लाएगी।
- सोयाबीन पर प्रति क्विंटल 6000 रुपए की एमएसपी प्रदान की जाएगी और सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाली लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाते हुए महायुति सरकार महाराष्ट्र में 50 लाख लखपति दीदी बनाएगी, जिसके लिए 500 स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- कई औद्योगिक तंत्र बनाए जाएंगे, जिसके लिए 1 हज़ार करोड़ रुपए का फंड हर वर्ष दिया जाएगा।
- अक्षय अन्न योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाले मुफ़्त राशन में चावल, ज्वार, मूंगफली, तेल, नमक, हल्दी, सरसों, जीरा और मसालों को सम्मिलित किया जाएगा।
- कौशल जनगणना का सबसे पहला प्रयोग महाराष्ट्र में किया जाएगा और प्रतिभा के अनुसार उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र बनाएंगे, जिससे 10 लाख नए उद्यमियों का निर्माण होगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से आने वाले लोगों को उद्यमी व्यवसाय लगाने के लिए 15 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- ओबीसी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एनटी और वीजेएनटी के पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
- महाराष्ट्र में मौजूद राज्य के गौरव के प्रतीक किलो को संरक्षण के लिए किला विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा।
- वृद्धजनों के लिए प्राथमिकता नीति अपनाई जाएगी, जिसके लिए आधार सक्षम सेवा नीति वितरण को लागू किया जाएगा।
- जबरन और धोखाधड़ी कर धर्मांतरण के खिलाफ एक मजबूत कानून बनाया जाएगा।
- कृषि एवं मानव बस्ती क्षेत्रों में वन्यजीवों के कारण होने वाली जान-माल की हानि को रोकने तथा मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए एआई, ड्रोन और रेडियो कॉलर जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र महाराष्ट्र के हर वर्ग, क्षेत्र, आयु और सामाजिक वर्ग के सुझावों को लेकर बनाया गया है। यह संकल्प पत्र महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का घोष है। महाराष्ट्र में जब भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनती है, तो महाराष्ट्र आगे बढ़ता है और जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली अघाड़ी की सरकार आती है, तो केवल राजनीति की जाती है। महाराष्ट्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र जो देश का प्रमुख राज्य और हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की सरकार बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन को कमल, धनुष और घड़ी के निशान पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। ■

'वन रैंक वन पेंशन' योजना से 25 लाख से अधिक भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिला लाभ

'वन रैंक वन पेंशन' सही मायनों में हमारे भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व-सैन्य कर्मियों के साहस एवं बलिदान के सम्मान में दी गई एक श्रद्धांजलि थी, जो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) को लागू करने का निर्णय लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने और अपने सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था— प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भारत सरकार ने पेंशन भत्तों में लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना शुरू की, यह एक ऐसा निर्णय है जो अपने सेवानिवृत्त होने सैन्य कर्मियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। सेवानिवृत्त सैनिकों ने वर्षों तक न केवल युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी थी, बल्कि अपनी सेवा देने के बाद के जीवन में भी समान अधिकार के लिए संघर्ष किया, विशेषकर जब पेंशन में मिलने वाले लाभ की बात आई। केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की शुरुआत के साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया कि जिन सैनिकों ने अटूट समर्पण के साथ देश की सेवा की है, उनके साथ उचित व्यवहार किया जाएगा।

इस पहल ने उन सिपाहियों के बलिदान एवं सेवा का सम्मान करने की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को व्यक्त किया, जिन्होंने देश की रक्षा की थी। इस शुरुआत ने पूर्व सैनिकों को वह सम्मान और वित्तीय सुरक्षा देने का वादा किया था, जिसके वे हकदार थे।

अब वन रैंक वन पेंशन योजना वर्ष 2024 में अपने 10 साल पूरे कर रही है, ऐसे में इस योजना से सशस्त्र बल समुदाय को होने वाले तमाम फायदों पर विचार करना आवश्यक है। इस पहल ने न केवल वर्तमान और पूर्व सेवानिवृत्त सैनिकों के बीच पेंशन के अंतर को पाट दिया है, बल्कि अपने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु देश के समर्पण को भी विस्तारित किया है। ओआरओपी ने पेंशन लाभों में समानता और निष्पक्षता लाकर भारत सरकार तथा देश के सैन्य कर्मियों के बीच संबंधों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वन रैंक वन पेंशन योजना की शुरुआत लाखों पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए परिवर्तनकारी साबित हुई है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि सेवानिवृत्ति के बाद के पूरे जीवन में सैन्य कर्मियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा।

'वन रैंक वन पेंशन' का अवलोकन

इसके मूल में जाकर देखें तो वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) एक सरल लेकिन गहन विचार है। समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सैन्य कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्ति की

तिथि की परवाह किए बिना समान पेंशन मिलनी चाहिए। यह सिद्धांत मुद्रास्फीति, वेतनमान में परिवर्तन और समय के साथ सेवा शर्तों की बदलती प्रकृति के कारण पूर्व सैनिकों के समक्ष पेंशन लाभों में आने वाली असमानता को दूर करता है।

यह योजना वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मियों के बीच पेंशन अंतर को समय-समय पर पाटना सुनिश्चित करके पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाती है। साल 2014 में वन रैंक वन पेंशन का सफल कार्यान्वयन न केवल एक नीतिगत बदलाव था, बल्कि देश की सेवा करने वालों के प्रति सरकार की कृतज्ञता व सम्मान प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी था।

वन रैंक वन पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं

केंद्र सरकार द्वारा 7 नवंबर, 2015 को जारी किये गए आदेश ने सभी सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए एक समान पेंशन प्रणाली लागू की गई, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि समान रैंक और समान सेवा

अवधि के साथ समान पेंशन लाभ मिलेगा। इस नीति के प्राथमिक तत्वों में शामिल हैं:

1. **पेंशन का पुनर्निर्धारण:** सभी पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन 2013 में सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की पेंशन के आधार पर 1 जुलाई, 2014 से पुनः निर्धारित की गई है। इससे पेंशन के लिए एक नया मानक स्थापित हुआ, जिसमें सभी सेवानिवृत्त हुए सैनिकों को उनकी सेवा के लिए समान लाभ मिलेगा।
2. **आवधिक संशोधन:** पेंशन को हर पांच साल में पुनः निर्धारित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वेतन और पेंशन संरचना में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करती रहे।
3. **बकाया भुगतान:** पेंशन की बकाया राशि का भुगतान समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में किया जाना था, हालांकि पारिवारिक पेंशनभोगियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए बकाया राशि का भुगतान एक ही किश्त में किया गया।
4. **औसत से अधिक पेंशन की सुरक्षा:** औसत से अधिक पेंशन पाने वाले कार्मिकों की पेंशन सुरक्षित रखी जाती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे ओआरओपी के लाभ से वंचित न हो जाएं।
5. **सभी पूर्व सैनिकों का समावेशन:** यह आदेश 30 जून, 2014 तक सेवानिवृत्त हुए सभी कार्मिकों हेतु लागू था और इसमें पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित सभी रैंकों के लिए पेंशन संशोधन के उद्देश्य से एक सशक्त ढांचा प्रदान किया गया था।

लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना

वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) की मांग लंबे समय से चला आ रहा एक मुद्दा था, जो 40 वर्षों से अधिक समय से लंबित था। कई सरकारी समितियों और आयोगों ने इस मामले में कार्य किया था, लेकिन हर बार मुख्य रूप से वित्तीय बाधाओं व प्रशासनिक जटिलताओं के कारण प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता था। तीसरा केंद्रीय वेतन आयोग इस मुद्दे पर पहला ऐसा आयोग था, जिसने मामले को गंभीरता से समझा तथा पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा में महत्व की सिफारिश की। इन वर्षों में केपी सिंह देव समिति (1984) और शरद पवार समिति (1991) जैसे समूहों ने भी इस मामले का अध्ययन किया, लेकिन ये भी कोई निश्चित समाधान पेश करने में विफल रहे। इन असफलताओं के बावजूद मांग लगातार बनी रही और रक्षा संबंधी स्थायी समिति तथा अन्य मंचों पर इसके कार्यान्वयन की वकालत जारी रही।

16वीं लोकसभा के आते-आते और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पूर्व सैनिकों की मांगों का सम्मान करने का निर्णय लिया। साल 2014 के बजट में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और फिर व्यापक विचार-विमर्श के बाद सरकारी आदेश 7 नवंबर, 2015 को पारित हो गया था, जिसके अंतर्गत 30 जून, 2014 तक सेवानिवृत्त हुए सभी सैन्य कर्मियों को शामिल किया गया था।

पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों पर योजना का प्रभाव

ओआरओपी योजना से 25 लाख से अधिक भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ मिला है, जिससे भूतपूर्व सैनिक समुदाय को अत्यंत आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हुई है। इस योजना से न केवल सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, बल्कि राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा का सम्मान भी सुनिश्चित हुआ है। कई भूतपूर्व रक्षा कर्मियों के लिए यह उनके योगदान की लंबे समय से प्रतीक्षित मान्यता थी, जो उनके बलिदान और सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त पुरस्कारों के बीच की खाई को पाटती थी।

ओआरओपी का आवश्यक रूप सामाजिक एवं भावनात्मक महत्व भी है। इसने भारत सरकार और इसके सैन्य कर्मियों के बीच सशक्त संबंध स्थापित करने में अपना योगदान दिया है, जो देश की संप्रभुता की रक्षा एवं सेवा करने वाले लोगों के प्रति राष्ट्र की वचनबद्धता को दर्शाता है। सैनिकों के ऐसे परिवारों के लिए जिनमें से तो कई अपने प्रियजनों के बलिदान के साथ जी रहे हैं, यह नीति पूर्णता और स्वीकृति की भावना लेकर आई है।

> भारत सरकार और इसके सैन्य कर्मियों के बीच सशक्त संबंध स्थापित करने में अपना योगदान दिया है

योजना का भविष्य: ओआरओपी की निरंतर प्रासंगिकता

एक दशक पहले जिस तरह से आज के ही दिन ओआरओपी को लागू किया गया था, तो रक्षा बलों के लिए इस नीति के निरंतर महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। जैसाकि स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि ओआरओपी योजना केवल पेंशन से ही संबंधित नहीं है, बल्कि यह सशस्त्र बलों को मजबूत करने और राष्ट्र की निःस्वार्थ सेवा करने वालों के कल्याण को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी है।

हर पांच साल में पेंशन का पुनर्निर्धारण यह सुनिश्चित करता है कि यह योजना पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुकूल बनी रहे। यह देश के सैन्य कर्मियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार के समर्पण का एक शक्तिशाली हस्ताक्षर भी है, जिनमें से कई भारत की सीमाओं तथा हितों की रक्षा में सबसे आगे हैं।

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि जब हम वन रैंक वन पेंशन के प्रभाव पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस नीति ने भारत के भूतपूर्व रक्षाकर्मियों को बहुत आवश्यक लाभ और सम्मान प्रदान किया है। निरंतर परिशोधन व आवधिक संशोधनों के साथ वन रैंक वन पेंशन योजना अपने सशस्त्र बलों के लिए देश के समर्थन की आधारशिला बने रहने का वादा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि भारत की संप्रभुता की रक्षा करने वाले सैन्य नायकों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी सम्मानित किया जाता है तथा उनकी देखभाल की जाती है। ■

कैबिनेट ने 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने को मंजूरी दी

इस निर्णय का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश भर के किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने छह नवंबर को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने को मंजूरी दे दी। इस निर्णय का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश भर के किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। यह रणनीतिक कदम किसानों को समर्थन देने और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एफसीआई ने 1964 में 100 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी और 4 करोड़ रुपये की इक्विटी के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। एफसीआई के संचालन में कई गुना वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी, 2023 में अधिकृत पूंजी 11,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये हो गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 में एफसीआई की इक्विटी 4,496 करोड़ रुपये थी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 10,157 करोड़ रुपये हो गई। अब, भारत सरकार ने एफसीआई के लिए 10,700 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण इक्विटी को मंजूरी दी है, जो इसे वित्तीय रूप से मजबूत करेगी और इसके परिवर्तन के लिए की गई पहलों को एक बड़ा बढ़ावा देगी।

एफसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्नों की खरीद, रणनीतिक खाद्यान्न भंडार के रखरखाव, कल्याणकारी उपायों के लिए खाद्यान्नों के वितरण और बाजार में खाद्यान्नों की कीमतों के स्थिरीकरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

गौरतलब है कि एमएसपी आधारित खरीद और एफसीआई की परिचालन क्षमताओं में निवेश के प्रति सरकार की दोहरी प्रतिबद्धता, किसानों को सशक्त बनाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतीक है। ■

2024-25 के दौरान 1647.05 लाख टन रिकार्ड खरीफ खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान

खरीफ चावल का उत्पादन 1199.34 लाख टन अनुमानित है जो पिछले वर्ष के खरीफ चावल उत्पादन से 66.75 लाख टन अधिक एवं औसत खरीफ चावल उत्पादन से 114.83 लाख टन अधिक है

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पांच नवंबर को जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख टन अनुमानित है जो पिछले वर्ष के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 89.37 लाख टन अधिक एवं औसत खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 124.59 लाख टन अधिक है। चावल, ज्वार और मक्का के अच्छे उत्पादन के कारण खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य कृषि फसलों (केवल खरीफ) के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं।

प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान खरीफ चावल का उत्पादन 1199.34 लाख टन अनुमानित है जो पिछले वर्ष के खरीफ चावल उत्पादन से 66.75 लाख टन अधिक एवं औसत खरीफ चावल उत्पादन से 114.83 लाख टन अधिक है। खरीफ मक्का का उत्पादन 245.41 लाख टन एवं खरीफ पोषक/मोटे अनाजों का उत्पादन 378.18 लाख टन अनुमानित है। इसके अलावा, 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनों का उत्पादन 69.54 लाख टन अनुमानित है।

2024-25 के दौरान देश में कुल खरीफ तिलहन उत्पादन 257.45 लाख टन अनुमानित है जोकि पिछले वर्ष के खरीफ तिलहन उत्पादन की तुलना में 15.83 लाख टन अधिक है। वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ मूंगफली का उत्पादन 103.60 लाख टन एवं सोयाबीन का उत्पादन 133.60 लाख टन अनुमानित है। 2024-25 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन 4399.30 लाख टन अनुमानित है। कपास का उत्पादन 299.26 लाख गांठें (प्रति गांठ 170 किग्रा.) अनुमानित है। पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन 84.56 लाख गांठें (प्रति गांठ 180 किग्रा) अनुमानित है।

विभिन्न खरीफ फसलों के उत्पादन निम्न है:

- **कुल खरीफ खाद्यान्न – 1647.05 लाख टन (रिकार्ड)**
- **चावल – 1199.34 लाख टन (रिकार्ड)**
- मक्का – 245.41 लाख टन (रिकार्ड)
- पोषक/मोटे अनाज – 378.18 लाख टन
- **कुल दलहन – 69.54 लाख टन**
- तूर – 35.02 लाख टन
- उड़द – 12.09 लाख टन
- मूंग – 13.83 लाख टन
- **कुल तिलहन – 257.45 लाख टन**
- मूंगफली – 103.60 लाख टन
- सोयाबीन – 133.60 लाख टन
- गन्ना – 4399.30 लाख टन
- कपास – 299.26 लाख गांठें (प्रति गांठ 170 कि. ग्रा.)
- पटसन एवं मेस्ता – 84.56 लाख गांठें (प्रति गांठ 180 कि. ग्रा.) ■

मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मिली मंजूरी

एक मिशन मोड वाला तंत्र देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण प्रदान करना सुविधाजनक व सहज बनाएगा और हर वर्ष 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को कवर करेगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने छह नवंबर को केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना पीएम विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दे दी। इस नई योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वित्तीय बाधाएं किसी को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोकें। पीएम विद्यालक्ष्मी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से निकली एक और महत्वपूर्ण पहल है, जिसने यह सिफारिश की थी कि सार्वजनिक और निजी, दोनों प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में विभिन्न उपायों के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेने वाला कोई भी विद्यार्थी ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों को कवर करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गिरवी मुक्त एवं गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा। यह योजना एक सरल, पारदर्शी एवं विद्यार्थियों के अनुकूल प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी, जो अंतर-संचालनीय और पूरी तरह से डिजिटल होगी। पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की प्रमुख बातें निम्न हैं:

- एक मिशन मोड वाला तंत्र देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण प्रदान करना सुविधाजनक व सहज बनाएगा और हर वर्ष 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को कवर करेगा
- एक विशेष ऋण उत्पाद गिरवी मुक्त एवं गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण को संभव बनाएगा; इसे एक सरल, पारदर्शी, विद्यार्थियों के अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सुलभ बनाया गया है
- कुल 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी, ताकि बैंकों को कवरेज बढ़ाने में सहायता मिल सके
- इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों के लिए यह योजना 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज छूट भी प्रदान करेगी
- यह 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को पहले से दी गई पूर्ण ब्याज छूट के अतिरिक्त है
- पीएम विद्यालक्ष्मी युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को अधिकतम सुलभ बनाने हेतु पिछले दशक में की गई विभिन्न पहलों के दायरे एवं सुलभता को आगे बढ़ाएगी ■

वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में प्रमुख खनिजों और अलौह धातुओं के उत्पादन में मजबूत वृद्धि

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक, परिष्कृत तांबे में शीर्ष-10 उत्पादकों में से एक और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है

केन्द्रीय खान मंत्रालय द्वारा एक नवंबर को जारी बयान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड उत्पादन स्तर पर पहुंचने के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कुछ प्रमुख खनिजों के उत्पादन में निरंतर मजबूत वृद्धि देखी गई है। मूल्य के हिसाब से कुल एमसीडीआर खनिज उत्पादन में लौह अयस्क का हिस्सा लगभग 70 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का उत्पादन 274 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था।

अनंतिम आंकड़ों के अनुसार लौह अयस्क का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल-सितंबर) में 128 एमएमटी से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल-सितंबर) में 135 एमएमटी हो गया है, जो 5.5 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्शाता है। मैंगनीज अयस्क का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल-सितंबर) में 6.2 प्रतिशत बढ़कर 1.7 एमएमटी हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1.6 एमएमटी था।

अलौह धातु क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल-सितंबर) में प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल-सितंबर) में 20.66 एलटी से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल-सितंबर) में 20.90 लाख टन (एलटी) हो गया। इसी तुलनात्मक अवधि के दौरान परिष्कृत तांबे का उत्पादन 2.39 एलटी से 4.6 प्रतिशत बढ़कर 2.50 एलटी हो गया है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक, परिष्कृत तांबे में शीर्ष-10 उत्पादकों में से एक और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। चालू वित्तीय वर्ष में लौह अयस्क के उत्पादन में निरंतर वृद्धि उपयोगकर्ता उद्योग यानी इस्पात में मजबूत मांग की स्थिति को दर्शाती है। एल्युमीनियम और तांबे में वृद्धि के साथ ये वृद्धि रुझान ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, निर्माण, ऑटोमोटिव और मशीनरी जैसे उपयोगकर्ता क्षेत्रों में निरंतर मजबूत आर्थिक गतिविधि की ओर संकेत करते हैं। ■

भारत के रतन का जाना...

नरेन्द्र मोदी

आज (9 नवंबर, 2024) श्री रतन टाटा जी के निधन को एक महीना हो रहा है। पिछले महीने आज के ही दिन जब मुझे उनके गुजरने की खबर मिली, तो मैं उस समय आसियान समिट के लिए निकलने की तैयारी में था। रतन टाटा जी के हमसे दूर चले जाने की वेदना अब भी मन में है। इस पीड़ा को भुला पाना आसान नहीं है। रतन टाटा जी के तौर पर भारत ने अपने एक महान सपूत को खो दिया है...एक अमूल्य रत्न को खो दिया है।

आज भी शहरों, कस्बों से लेकर गांवों तक, लोग उनकी कमी को गहराई से महसूस कर रहे हैं। हम सबका ये दुःख साझा है। चाहे कोई उद्योगपति हो, उभरता हुआ उद्यमी हो या कोई प्रोफेशनल हो, हर किसी को उनके निधन से दुःख हुआ है। पर्यावरण रक्षा से जुड़े लोग...समाज सेवा से जुड़े लोग भी उनके निधन से उतने ही दुःखी हैं। और ये दुःख हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महसूस कर रहे हैं।

युवाओं के लिए श्री रतन टाटा एक प्रेरणास्रोत थे। उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व हमें याद दिलाता है कि कोई सपना ऐसा नहीं जिसे पूरा ना किया जा सके, कोई लक्ष्य ऐसा नहीं जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके। रतन टाटा जी ने सबको सिखाया है कि विनम्र स्वभाव के साथ, दूसरों की मदद करते हुए भी सफलता पाई जा सकती है।

रतन टाटा जी, भारतीय उद्यमशीलता की बेहतरीन परंपराओं के प्रतीक थे। वो विश्वसनीयता, उत्कृष्टता और बेहतरीन सेवा जैसे मूल्यों के अडिग प्रतिनिधि थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह दुनिया भर में सम्मान, ईमानदारी और विश्वसनीयता का प्रतीक बनकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। इसके बावजूद, उन्होंने अपनी उपलब्धियों को पूरी विनम्रता और सहजता के साथ स्वीकार किया।

दूसरों के सपनों का खुलकर समर्थन करना, दूसरों के सपने पूरा करने में सहयोग करना, ये श्री रतन टाटा के सबसे शानदार गुणों में से एक था। हाल के वर्षों में वो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का मार्गदर्शन करने और भविष्य की संभावनाओं से भरे उद्यमों में निवेश करने के लिए जाने गए। उन्होंने युवा आंत्रप्रेन्योर की आशाओं और आकांक्षाओं को समझा, साथ ही भारत के भविष्य को आकार देने की उनकी क्षमता को पहचाना।

भारत के युवाओं के प्रयासों का समर्थन करके उन्होंने नए सपने देखने वाली नई पीढ़ी को जोखिम लेने और सीमाओं से परे जाने का हौसला दिया। उनके इस कदम ने भारत में इनोवेशन और आंत्रप्रेन्योरशिप की संस्कृति विकसित करने में बड़ी मदद की है। आने वाले दशकों में हम भारत पर इसका सकारात्मक प्रभाव जरूर देखेंगे।

रतन टाटा जी ने हमेशा बेहतरीन क्वालिटी के प्रॉडक्ट...बेहतरीन क्वालिटी की सर्विस पर जोर दिया और भारतीय उद्यमों को ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करने का रास्ता दिखाया।

क्वालिटी की सर्विस पर जोर दिया और भारतीय उद्यमों को ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करने का रास्ता दिखाया। आज जब भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो हम ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करते हुए ही दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं। मुझे आशा है कि उनका ये विजन हमारे देश की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और भारत वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लिए अपनी पहचान मजबूत करेगा।

रतन टाटा जी की महानता बोर्डरूम या सहयोगियों की मदद करने तक ही सीमित नहीं थी। सभी जीव-जंतुओं के प्रति उनके मन में करुणा थी। जानवरों के प्रति उनका गहरा प्रेम जगजाहिर था और वे पशुओं के कल्याण पर केन्द्रित हर प्रयास को बढ़ावा देते थे। वो अक्सर अपने डॉग्स की तस्वीरें साझा करते थे, जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। मुझे याद है, जब रतन टाटा जी को लोग आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ रहे थे...तो उनका डॉग 'गोवा' भी वहां नम आंखों के साथ पहुंचा था।

रतन टाटा जी का जीवन इस बात की याद दिलाता है कि लीडरशिप का आकलन केवल उपलब्धियों से ही नहीं किया जाता है, बल्कि सबसे कमजोर लोगों की देखभाल करने की उसकी क्षमता से भी किया जाता है।

रतन टाटा जी ने हमेशा नेशन फर्स्ट की भावना को सर्वोपरि रखा। 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद उनके द्वारा मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल को पूरी तत्परता के साथ फिर से खोलना, इस राष्ट्र के एकजुट होकर उठ खड़े होने का प्रतीक था। उनके इस कदम ने बड़ा संदेश दिया कि – भारत रुकेगा नहीं...भारत निडर है और आतंकवाद के सामने झुकने से इनकार करता है।

व्यक्तिगत तौर पर मुझे पिछले कुछ दशकों में उन्हें बेहद करीब से जानने का सौभाग्य मिला। हमने गुजरात में साथ मिलकर काम किया। वहां उनकी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। इनमें कई

ऐसी परियोजनाएं भी शामिल थीं, जिसे लेकर वे बेहद भावुक थे।

जब मैं केन्द्र सरकार में आया, तो हमारी घनिष्ठ बातचीत जारी रही और वो हमारे राष्ट्र-निर्माण के प्रयासों में एक प्रतिबद्ध भागीदार बने रहे। स्वच्छ भारत मिशन के प्रति श्री रतन टाटा का उत्साह विशेष रूप से मेरे दिल को छू गया था। वह इस जन आंदोलन के मुखर समर्थक थे। वह इस बात को समझते थे कि स्वच्छता और स्वस्थ आदतें भारत की प्रगति की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण हैं। अक्टूबर की शुरुआत में स्वच्छ भारत मिशन की दसवीं वर्षगांठ के लिए उनका वीडियो संदेश मुझे अभी भी याद है। यह वीडियो संदेश एक तरह से उनकी अंतिम सार्वजनिक उपस्थितियों में से एक रहा है।

कैंसर के खिलाफ लड़ाई एक और ऐसा लक्ष्य था, जो उनके दिल के करीब था। मुझे दो साल पहले असम का वो कार्यक्रम याद आता है, जहां हमने संयुक्त रूप से राज्य में विभिन्न कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया था। उस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो अपने जीवन के आखिरी वर्षों को हेल्थ सेक्टर को समर्पित करना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवा एवं कैंसर संबंधी देखभाल को सुलभ और किफायती बनाने के उनके प्रयास इस बात के प्रमाण हैं कि वो बीमारियों से जूझ रहे लोगों के प्रति कितनी गहरी संवेदना रखते थे।

मैं रतन टाटा जी को एक विद्वान व्यक्ति के रूप में भी याद करता हूं - वह अक्सर मुझे विभिन्न मुद्दों पर लिखा करते थे, चाहे वह शासन से जुड़े मामले हों, किसी काम की सराहना करना हो या फिर चुनाव में जीत के बाद बधाई सन्देश भेजना हो।

अभी कुछ सप्ताह पहले मैं स्पेन सरकार के राष्ट्रपति श्री पेड्रो सान्चेज के साथ वडोदरा में था और हमने संयुक्त रूप से एक विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस फैक्ट्री में सी-295 विमान भारत में बनाए जाएंगे। श्री रतन टाटा ने ही इस पर काम शुरू किया था। उस समय मुझे श्री रतन टाटा की बहुत कमी महसूस हुई।

आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो हमें उस समाज को भी याद रखना है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। जहां व्यापार, अच्छे कार्यों के लिए एक शक्ति के रूप में काम करे, जहां प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता को महत्व दिया जाए और जहां प्रगति का आकलन सभी के कल्याण और खुशी के आधार पर किया जाए। रतन टाटा जी आज भी उन जिंदगियों और सपनों में जीवित हैं, जिन्हें उन्होंने सहारा दिया और जिनके सपनों को साकार किया। भारत को एक बेहतर, सहृदय और उम्मीदों से भरी भूमि बनाने के लिए आने वाली पीढ़ियां उनकी सदैव आभारी रहेंगी। ■

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

श्रद्धांजलि

जम्मू-कश्मीर के विधायक देवेन्द्र सिंह राणा नहीं रहे

प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जम्मू-कश्मीर के नगरोटा विधानसभा से मौजूदा विधायक श्री देवेन्द्र सिंह राणा का 31 अक्टूबर, 2024 को 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका फरीदाबाद (हरियाणा) के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के विधायक श्री देवेन्द्र सिंह राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, "श्री देवेन्द्र सिंह राणा जी का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है। वह पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे। श्री राणा ने जम्मू-कश्मीर की प्रगति के लिए पूरी लगन से काम किया। उन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव जीता था एवं जम्मू-कश्मीर में भाजपा को मजबूत बनाने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं।"

श्री राणा केन्द्रीय मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह के छोटे भाई थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में श्री राणा ने नगरोटा सीट पर जीत हासिल की थी, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जेकेएनसी के जोगिंदर सिंह को 30,472 मतों के बड़े अंतर से हराया था।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, "वरिष्ठ भाजपा नेता एवं नगरोटा से विधायक श्री देवेंद्र सिंह राणा जी के असामयिक निधन से गहरा दुःख हुआ। जनसेवा के प्रति उनका समर्पण और जम्मू-कश्मीर के लोगों के विकास के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके परिवार एवं समर्थकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।" ■

मोदी स्टोरी

स्वामी विवेकानंद के शिकागो में दिए ऐतिहासिक भाषण के शताब्दी वर्ष समारोह में नरेन्द्र मोदी जी की भागीदारी

—हसमुख पटेल, एनआरआई-अमेरिका

विश्व हिंदू परिषद् ने अमेरिका में वर्ष 1993 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण के 100 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर युवा नरेन्द्र मोदी को एक उभरते हुए राजनेता के रूप में अमेरिका आमंत्रित किया गया था। इस दौरान श्री नरेन्द्र मोदी के साथ रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री हसमुख पटेल ने इस यात्रा को याद करते हुए बताया कि उस समय संघ के प्रचारक रहे श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया था। यह सभा एक बड़े हॉल में आयोजित की गई थी, जहां एक प्रतीकात्मक मार्च का आयोजन किया गया था।

मार्च का नेतृत्व करते हुए एक स्वयंसेवक ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उठाया हुआ था और घोष (संघ संगीत बैंड) के पारंपरिक संगीत ने हवा को ताजगी से भर दिया था। श्री पटेल ने कहा कि यह कार्यक्रम एक भव्य आयोजन था, जिसमें 15,000-20,000 लोग शामिल हुए। युवाओं को संगठित करने और उन्हें प्रेरित करने में श्री मोदी की भूमिका के कारण भी इस समारोह ने एक अमिट छाप छोड़ी। श्री हसमुख पटेल ने कहा कि इस कार्यक्रम में उनकी भागीदारी स्वामी विवेकानंद के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। ■

कमल पुष्प

सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

रेबती बिस्वास

श्री रेबती बिस्वास का जन्म बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में हुआ था, लेकिन बाद में वह अंडमान के डिगलीपुर गांव में आकर बस गये थे। श्री बिस्वास 21 वर्ष की अल्पायु में ही गोपाल जी महाराज के शिष्य बने, इसके बाद वह हिंदू धर्म के और करीब आ गए। श्री बिस्वास भाजपा की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और 1990 में श्री बिष्णु पद के नेतृत्व में वह पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने अकेले ही देश के सबसे उत्तरी द्वीप डिगलीपुर में भाजपा को मजबूत करने का दायित्व उठाया। दूरदराज के इलाकों में जाकर उन्होंने लोगों को भाजपा के बारे में जागरूक किया और अंततः कई लोग संगठन के कार्यकर्ता और समर्थक बन गए। वर्ष 1996 में श्री बिस्वास के अथक प्रयासों से भाजपा उम्मीदवार श्री बिष्णु पद सांसद बनें। 2013 में किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष किया कि डिगलीपुर के किसानों को समय पर खाद मिले। इसके अलावा उन्होंने साल भर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए कलपोंग नदी पर बांध बनाने का सुझाव दिया। श्री रेबती बिस्वास को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया। वर्ष 2005 में वह डिगलीपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत पंचायत समिति के सदस्य भी चुने गए। उन्होंने पार्टी के लिए काम करना अधिक पसंद किया। ■

रेबती बिस्वास

जन्मः 01 जनवरी, 1959

सक्रिय वर्षः 2013-2014

जिलाः पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह

भारत की रक्षा क्रांति उड़ान भर रही है!

नरेन्द्र मोदी

कल (29 अक्टूबर) का दिन भारत की रक्षा एवं एयरोस्पेस यात्रा में एक महत्वपूर्ण पल था, जब हमने स्पेन के राष्ट्रपति और मेरे मित्र श्री पेड्रो सांचेज के साथ वडोदरा में सी-295 विमान निर्माण परिसर का उद्घाटन किया।

हमारी कार्यान्वयन की गति आश्चर्यजनक रही है— आधारशिला रखे जाने से लेकर परिचालन सुविधा शुरू होने में सिर्फ दो वर्षों का समय! यह एक नई कार्य-संस्कृति और भारत के लोगों की क्षमताओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

भारत की इस सफलता को आंकड़ों में देखा जा सकता है:

- रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये (2023-24) हो गया है।
- रक्षा निर्यात 2014 में 1,000 करोड़ रुपये से बढ़कर आज 21,000 करोड़ रुपये हो गया है।
- सिर्फ 3 साल में 12,300 से ज्यादा वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया गया है।
- डीपीएसयू द्वारा घरेलू विक्रेताओं में 7,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया गया है।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत उद्योग-आधारित नवाचार के लिए रखा गया है।

लेकिन आंकड़ों के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सभी को खुशी प्रदान कर रही हैं।

संपूर्ण रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हो रहा है:

1. विनिर्माण सफलता:

- स्वदेशी युद्धपोत हमारे जलक्षेत्र में गश्त कर रहे हैं
- भारत में निर्मित मिसाइलें हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर रही हैं
- घरेलू स्तर पर निर्मित बुलेटप्रूफ जैकेट हमारे सैनिकों की रक्षा कर रही हैं
- हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं और रक्षा उपकरण निर्माता के रूप में शीर्ष स्थान पर आने के लिए भी काम कर रहा है

2. रणनीतिक अवसंरचना:

- उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में दो आधुनिक रक्षा गलियारों का निर्माण।

3. नवाचार पहल:

- iDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार) एक संपूर्ण स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बना रहा है।
- एमएसएमई रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बन रहे हैं
- उद्योग-अकादमिक भागीदारी, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दे रही है

हमारी युवा शक्ति की ताकत और कौशल तथा सरकार के प्रयासों के कारण हम निम्नलिखित प्रभाव देख रहे हैं:

- आयात निर्भरता में कमी
- रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
- युवाओं के लिए कौशल विकास
- रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा मिल रहा है

एक समय वह था, जब हमारी सेनाओं को आवश्यक उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ता था; उससे लेकर आज के आत्मनिर्भरता के युग तक; यह एक ऐसी यात्रा है जिस पर हर भारतीय गर्व कर सकता है।

आह्वान:

हमारे युवाओं, स्टार्टअप्स, निर्माताओं और नवोन्मेषकों के लिए— भारत का रक्षा क्षेत्र आह्वान कर रहा है! इतिहास का हिस्सा बनने का यह आपका समय है। भारत को आपकी विशेषज्ञता एवं उत्साह की आवश्यकता है।

नवाचार के लिए दरवाजे खुले हैं, नीतियां सहायक हैं, और अवसर अभूतपूर्व हैं। हम सब मिलकर भारत को न केवल रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि रक्षा विनिर्माण में वैश्विक नेतृत्वकर्ता भी बनेंगे।

आइए, हम सब मिलकर एक मजबूत, 'आत्मनिर्भर भारत' का निर्माण करें! ■

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

झूठे वादों की एक अंतहीन गाथा

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस झूठे वादों और कुशासन का पर्याय बन गई है। हर राज्य एवं राष्ट्रीय चुनाव से पहले पार्टी लोगों के सामने अपने वादे और योजनाएं पेश करती है, ताकि चुनावों के बाद सरकार बनने पर जनता को धोखा दे सके। जब वह ऋण माफी का वादा करते हैं, तो वह धन की कमी की शिकायत करते हुए उसे पूरा नहीं करते। उनके द्वारा शुरू किए गए हर मुफ़्त कार्यक्रम की स्थिरता अनिश्चित है, जैसाकि वर्तमान में जिन राज्यों में उनका शासन हैं, वहां यह स्पष्ट है। कांग्रेस के शासन में नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आरंभ करना तो दूर की कोड़ी है, क्योंकि वहां पहले से चल रही परियोजनाओं को भी अनिश्चित काल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को असुविधा होती है। कांग्रेस के बारे में अगर कोई एक स्थिर बात है तो वह यह कि वह अपने वादों को पूरा करने में विफल होने पर बहाने बनाने में अव्वल रहती हैं। उसके पास सबसे आसान उपाय केंद्र को दोषी ठहराना है, जैसाकि आज कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश की सरकारें कर रही हैं। अपने राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य के साथ वादों को पूरा करने में असमर्थ कांग्रेस, अपने झूठे वादों के लिए पिछली सरकारों के काम को जिम्मेदार ठहराती है, जैसाकि तेलंगाना में देखा गया है।

जिन राज्यों में वह सत्ता में थे, वहां मानक फॉर्मूला यह था कि चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे किए जाएं, लेकिन बाद में उन्हें भूला दिया जाए। राजस्थान में कांग्रेस के स्वास्थ्य कार्यक्रम को जनता के बीच बहुत धूमधाम से ले जाया गया, लेकिन जब इसका क्रियान्वयन किया गया तो लोगों को केवल निराशा ही हाथ लगी। झूठे वादे कांग्रेस के नेतृत्व के लिए भी एक सीख हैं, जो बताती है कि पार्टी जवाबदेही एवं विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतर रही है। 2024 के चुनावों के बाद कांग्रेस के कई मतदाता पार्टी कार्यालयों के सामने कतार में खड़े हो गए, उनके पास कांग्रेस (नकली) के गारंटी कार्ड थे, जिसमें उन्हें 1,00,000 रुपये देने का वादा किया गया था। कांग्रेस के साथ ऐसे झूठे वादों का एक लंबा इतिहास है। 1970 के दशक में गरीबी हटाओ से लेकर 2024 में बेरोजगारी भत्ते के वादे तक और 1985 में शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने से लेकर 2006 में अल्पसंख्यकों को भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार देने का वादा करने तक, कांग्रेस ने भारतीय मतदाताओं को हल्के में लेने और उन्हें धोखा देने की कला में महारत हासिल कर ली है।

हिमाचल प्रदेश: न्याय नहीं, अन्याय है!

लाभार्थी	वादे	विफलता
आम जनता	सभी घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली	उपचुनाव पूर्ण होने के साथ ही योजना खत्म कर दी गई
दूध उत्पादक किसान	दूध खरीद दर 80-100 रुपये प्रति लीटर गाय का गोबर खरीद दर 2 रुपये प्रति किलो	दूध उत्पादक किसानों को मात्र 45-55 रुपये प्रति लीटर मिला गाय के गोबर पर अभी तक कोई राहत नहीं!
युवा	हर वर्ष 1 लाख नौकरियां और पांच साल में कुल 5 लाख नौकरियां	एक वर्ष में 1,300 युवाओं को भी नियमित नौकरियां नहीं दे पाए
पेंशनभोगी	पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वाद	कर्मचारियों को नियमित वेतन भी नहीं मिल रहा
महिलाएं	18 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह	पैसों की कमी का हवाला देते हुए महिलाओं को दिए जाने वाली राशि के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गयी
आम जनता	मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक	कांग्रेस के शासन में कोई नया क्लीनिक शुरू नहीं हुआ
टैक्सी चालक	टैक्सी परमिट 15 साल के होंगे	वादे किए गए, लेकिन परमिट नहीं दिए गए
युवा	युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये का राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप फंड	कोई नई नौकरी नहीं। इच्छुक उम्मीदवार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं

STATE IN PICS

THEN Vs. NOW

Fate of Youth in Himachal Pradesh

Students at Himachal University with CM, May 2023

Job aspirants protest outside CM's house, January 2024

कर्नाटक: न्याय नहीं, अन्याय है!

कर्नाटक रिपोर्ट कार्ड

लाभार्थी	वादे	विफलता
महिलाएं	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपये तक दिये जाएंगे	भुगतान में देरी और बढ़ोतरी का कोई आश्वासन नहीं-गरीबों की वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ा झटका
किसान	किसानों के लिए रोजाना 8 घंटे बिजली आपूर्ति	कांग्रेस के झूठे वादों ने किसानों को अंधेरे में रखा।
आम लोग	अन्नभाग्य योजना के तहत 10 किलो चावल	केवल प्रति व्यक्ति 170 रुपये यानी सिर्फ 5 किलो चावल देने का प्रावधान-कांग्रेस अपने वादे को पूरा नहीं कर पायी!
दूध उत्पादक किसान	दूध सब्सिडी 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए की जाएगी	कांग्रेस ने नंदिनी दूध की कीमत 3 रुपए बढ़ाई

Re-thinking of failed poll 'guarantees' underway

INDIA TODAY

Congress leaders want Karnataka government to 'rethink' guarantees after poll result

Fiscal Failure

THE ECONOMIC TIMES

Karnataka Budget: Congress regime resorts to borrowing to sustain guarantee schemes

Corruption

THE HINDU

Here is how Karnataka Chief Minister Siddaramaiah explained allotment of 14 alternative sites by MUDA to his wife Parvathi

Skewed Women Safety

NewsKarnataka

Rising Concern: 7,550 Women Missing in Karnataka in Six Months

Heavily Burdened KSRTC

KSRTC Faces Rs 295 Crore Loss, Plans 20 Per Cent Fare Hike To Stay Afloat As Shakti Scheme Increases Burden Jul 15, 2024

Farmer's Apathy

INDIA TODAY

Nearly 1,200 Karnataka farmers died by suicide in 15 months: Government

Belagavi district reported most of these cases with 122, while Haveri and Dharwad recorded 120 and 101 farmer suicide cases, respectively.

तेलंगाना: न्याय नहीं, अन्याय है!

तेलंगाना रिपोर्ट कार्ड		
लाभार्थी	**वादे**	**विफलता**
गिग और असंगठित श्रमिक	न्यूनतम वेतन, सभी को स्वास्थ्य बीमा, कल्याणकारी कानून लागू किया जाएगा।	न तो न्यूनतम वेतन और न ही स्वास्थ्य बीमा लागू किया गया, बल्कि आंकड़ों की कमी का बहाना बनाया गया। तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (अधिकार और कल्याण) विधेयक, 2024 अभी तक विधानसभा में पेश नहीं हो सका है।
आम जनता	महालक्ष्मी योजना (हर साल 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर)	योजना क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों में फंसी हुई है।
पिछड़ा वर्ग	गृह ज्योति योजना के तहत पिछड़े वर्ग, नए पावरलूम मालिकों और सैलून के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली	बिजली नहीं, केवल पावरप्ले।
किसान	17 प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम गारंटीकृत मूल्य दिए जाएंगे।	कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई। 17 फसलों पर कोई एमएसपी नहीं।
	2 लाख रुपये तक के कर्ज एक बार में माफ किए जाएंगे।	कांग्रेस ने चुनाव के बाद नई शर्तें लगा दी और लाभार्थी नौकरशाही की अड़चनों में फंस गए।
अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण	अनुसूचित जनजाति अत्याचार (रोकथाम) अधिनियम का सख्ती से क्रियान्वयन किया जाएगा— अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 3 विशेष निगमों का गठन किया जाएगा।	तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम रहीः कांग्रेस ने अपनी योजना बदली; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित धन को अल्पसंख्यक बजट में बदल दिया गया।
युवा	3,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता।	युवाओं का विरोध प्रदर्शन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रद्द किया गया, विज्ञापन बहुत हुआ, फिर भी भत्ते अभी भी नदारद
आम जनता	उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए नियमित प्रजा दरबार	प्रजा दरबार कुछ ही दिनों तक चला। मुख्यमंत्री ने इसमें केवल एक दिन भाग लिया।

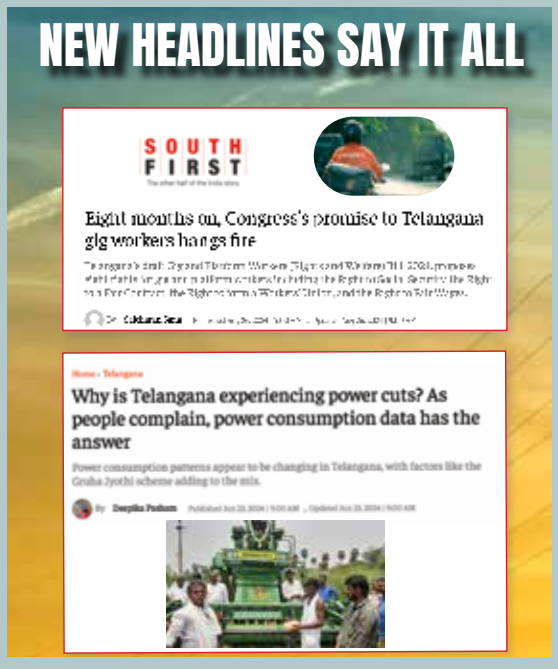

'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' न केवल नाम से बल्कि अपने निर्माण में भी एकता का प्रतीक है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लिया और सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने एकता दिवस की शपथ भी दिलाई और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दिवस परेड भी देखी। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "सरदार साहब के ओजस्वी शब्द...स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास यह कार्यक्रम...एकता नगर का यह मनोरम दृश्य...यहां आयोजित अद्भुत प्रदर्शन...मिनी इंडिया की यह झलक...सब कुछ इतना अद्भुत है...यह प्रेरित करने वाला है।" श्री मोदी ने सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह ही 31 अक्टूबर को यह आयोजन पूरे देश को नई ऊर्जा से भर देता है।

प्रधानमंत्री ने दीपावली के मौके पर देश और दुनिया में रहने वाले सभी भारतीयों को अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस, दीपावली के साथ-साथ एकता के इस उत्सव को मनाने का अद्भुत संयोग लेकर आया है। श्री मोदी ने कहा, "दीपावली, दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश को प्रकाशित करती है और अब दीपावली का उत्सव भारत को दुनिया से भी जोड़ रहा है।"

देश अगले 2 वर्षों तक सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाएगा

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि इस वर्ष का एकता दिवस और भी विशेष है, क्योंकि आज से सरदार पटेल की 150वीं जयंती का वर्ष शुरू हो रहा है। अगले 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाएगा। यह भारत के लिए उनके असाधारण योगदान के प्रति देश की श्रद्धांजलि है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दो वर्षों का यह उत्सव 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह अवसर हमें सिखाएगा, जो कार्य असंभव लगते हैं कड़ी मेहनत और लगन से वे संभव किए जा सकते हैं।

श्री मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने आक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए सभी को एकजुट किया। महाराष्ट्र का रायगढ़ किला आज भी वह कहानी कहता है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ किला सामाजिक न्याय, देशभक्ति और राष्ट्र प्रथम के मूल्यों की पावन भूमि रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, "छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले में राष्ट्र के विभिन्न विचारों को एक उद्देश्य के लिए एकजुट किया था। आज यहां एकता नगर में हम रायगढ़ के उस ऐतिहासिक किले की छवि देख रहे हैं...आज इस पृष्ठभूमि में हम एक विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए यहां एकजुट हुए हैं।"

श्री मोदी ने दोहराया कि पिछले एक दशक में भारत ने एकता और अखंडता को मजबूत करने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। यह प्रतिबद्धता विभिन्न सरकारी प्रयासों में स्पष्ट है, जिसका उदाहरण एकता नगर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। यह स्मारक न केवल नाम से बल्कि अपने निर्माण में भी एकता का प्रतीक है, क्योंकि इसे देश भर के गांवों से एकत्र किए गए लोहे और मिट्टी से बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकता नगर में एकता नर्सरी, हर महाद्वीप की वनस्पतियों वाला विश्व वन, देशभर के स्वस्थ खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने वाला चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, विभिन्न क्षेत्रों से आयुर्वेद को उजागर करने वाला आरोग्य वन और एकता मॉल है, जहां देश भर के हस्तशिल्प को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है।

श्री मोदी ने अपने भाषण की समाप्ति में सरदार पटेल को उद्धृत करते हुए देशवासियों से एकता के लिए प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हमें यह याद रखना है कि भारत विविधता का देश है और विविधता को बनाए रखते हुए एकता की भावना को मजबूत किया जा सकता है।" ■

टीकाकरण कार्यक्रम को सार्वभौमिक बनाने के लिए डिजिटल प्रयास

जगत प्रकाश नड्डा

विभिन्न बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की भूमिका वर्ष 1796 में ही साबित हो चुकी थी। यह वह समय था, जब खतरनाक चेचक के खिलाफ पहला टीकाकरण अभियान चलाया गया था। पिछले 50 वर्षों में ही टीकाकरण कार्यक्रमों ने दुनिया भर में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बचाई है, जो हर साल-हर मिनट छह लोगों की जान बचाने के बराबर है।

नागरिकों के जीवन की रक्षा करना भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के तहत हर साल 2.6 करोड़ से ज्यादा नवजात शिशुओं को खसरा, डिप्थीरिया और पोलियो जैसी 12 बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। ये जानलेवा हो सकती हैं या बच्चे के स्वास्थ्य एवं सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं।

यद्यपि इस कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में हुई थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसका तेजी से विस्तार हुआ है। मिशन इंद्रधनुष जैसे अभियानों ने टीकाकरण कवरेज को 90 प्रतिशत से अधिक कर दिया है। हालांकि, 100 प्रतिशत टीकाकरण कवरेज हासिल करने में हमारे सामने अभी भी चुनौतियां हैं, जिनमें कुछ क्षेत्रों एवं समुदायों में टीकाकरण की झिझक से लेकर पलायन के कारण कार्यक्रम से ड्रॉपआउट होना या अन्य कई कारक शामिल हैं, इसके परिणामस्वरूप कुछ बच्चे आंशिक रूप से इस टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनते है या उनको इस कार्यक्रम से वंचित रहना पड़ता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार सभी बच्चों एवं गर्भवती महिला को टीकाकरण के तहत लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक तकनीकी समाधान लेकर आया है, जिसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम-विन (यू-विन) कहा जाता है।

यू-विन, एक नाम-आधारित सुविधा है जो 'कहीं भी, कभी भी टीकाकरण' की सुविधा प्रदान करती है। इसे लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। यह प्लेटफ़ॉर्म टीकाकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है। गर्भवती महिलाएं यू-विन ऐप या पोर्टल के माध्यम से स्वयं पंजीकरण कर सकती हैं या पंजीकरण के लिए निकटतम टीकाकरण केंद्र में जा सकती हैं।

नागरिकों के जीवन की रक्षा करना भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के तहत हर साल 2.6 करोड़ से ज्यादा नवजात शिशुओं को खसरा, डिप्थीरिया और पोलियो जैसी 12 बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं

एक बार पंजीकृत होने के बाद स्वास्थ्य देखभाल कर्मी गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कार्यक्रम को ट्रैक कर सकते हैं, प्रसव के रिकॉर्ड रख सकते हैं, नवजात शिशु को पंजीकृत कर सकते हैं और उनके टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू कर सकते हैं। इस प्रकिया को स्वास्थ्य कर्मी द्वारा तब तक ट्रैक किया जा सकता है, जब तक बच्चा 16 वर्ष का न हो जाए।

यू-विन माता-पिता एवं अभिभावकों को सहूलियत प्रदान करता है, जिससे वे देश में कहीं भी टीकाकरण सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म अपॉइंटमेंट बुकिंग सुविधा भी प्रदान करता है, जो विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए उपयोगी है।

यू-विन 11 भाषाओं में उपलब्ध है, जो प्लेटफ़ॉर्म की पहुंच को विस्तार देता है। एक अन्य प्रमुख विशेषता रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण है। जब भी कोई सत्यापित लाभार्थी टीका प्राप्त करता है, तो एक वास्तविक समय डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड बनाया जाता है। लाभार्थियों को एक क्यूआर-आधारित प्रमाणपत्र भी मिलता है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है और ऑन-द्-गो सत्यापन के लिए मोबाइल उपकरणों पर संगृहीत किया जा सकता है। यह विशेष रूप से स्कूल में प्रवेश और यात्रा के लिए उपयोगी है।

इसके अतिरिक्त, प्लेटफ़ॉर्म आगामी टीकाकरण खुराक के लिए एसएमएस सूचनाएं भेजता है, यह सुनिश्चित करता है कि माता-पिता और स्वास्थ्य देखभाल कर्मी खुराक के बीच निर्धारित न्यूनतम अंतराल का पालन करें।

यू-विन एक इंटीग्रेटर के रूप में कार्य करता है, जो माता-पिता/अभिभावकों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य देखभाल कर्मी और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को एक ही मंच पर लाता है। यह पूरे देश में टीकाकरण कवरेज की प्रभावी निगरानी रखने की अनुमति देता है। यह लाभार्थियों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) और बाल आभा आईडी (ABHA ID) बनाने में सहयोग प्रदान करता है, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत सहमति के साथ संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य रिकॉर्ड

चिकित्सा पेशेवरों और अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा किये जा सकते हैं। इससे चिकित्सा पेशेवरों को एक नजर में व्यक्ति के चिकित्सा इतिहास को जानने में मदद मिलती है, जो रोगी को बेहतर परामर्श प्रदान करने में सहायक होता है। यू-विन एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को टीकाकरण की सूची बनाने में भी सहायता करता है, जिससे लाभार्थियों का समय पर टीकाकरण किया जा सकें।

पिछले 10 वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित स्वास्थ्य प्रणालियों पर भरोसा किया है। 2014 में शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) ने वैक्सीन प्राप्त करने, संग्रहीत करने और अंतिम मील तक वितरित करने के तरीके को बदल दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया ने भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की क्षमता को 'को-विन' कार्यक्रम की सफलता में देखा, जिसने 18 महीने से भी कम समय में 220 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक देने में मदद की। अब यू-विन टीकाकरण कवरेज में उल्लेखनीय सुधार करके देश में टीकाकरण सेवाओं के परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है।

जैसे-जैसे भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहा है, मजबूत टीकाकरण कार्यक्रमों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता सिर्फ़ एक स्वास्थ्य पहल नहीं है - यह भविष्य के लिए एक आधारभूत निवेश है। उन्नत डिजिटल बुनियादी ढांचे और व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों के माध्यम से अपने सबसे कम उम्र के नागरिकों के टीकाकरण को प्राथमिकता देकर, भारत न केवल रोकथाम योग्य बीमारियों का मुकाबला कर रहा है, बल्कि एक स्वस्थ आबादी को जन्म दे रहा है।

यह प्रयास एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं, जहां कोई भी बच्चा जीवन रक्षक टीकों के बिना न रहे, चाहे वे कहीं भी रहते हों।

(लेखक भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं)

कारीगरों का सम्मान: पीएम विश्वकर्मा योजना

पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है, जिसका वित्तीय परिव्यय पांच साल (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपये है

77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत भर के कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल का अनावरण किया—पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर, 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (द्वारका) में लॉन्च की गई यह योजना पारंपरिक शिल्प कौशल का समर्थन करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यह योजना अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में लगे कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को लक्षित करती है, जहां लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, बढ़ई जैसे कारीगर अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं। इन कारीगरों को विश्वकर्मा कहा जाता है। कारीगरों के ये कौशल अक्सर पीढ़ियों से आगे बढ़ते हैं, गुरु-शिष्य परंपरा का पालन करते हुए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देते हैं, जो सदियों पुरानी परंपराओं की निरंतरता को बढ़ावा देता है। कारीगरों के उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार पहुंच को बढ़ाकर पीएम विश्वकर्मा योजना इन कुशल व्यक्तियों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं दोनों में एकीकृत करना चाहती है।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चार नवंबर को जारी एक बयान के अनुसार अपनी शुरुआत के बाद से इस योजना के प्रति कारीगरों ने उल्लेखनीय रुचि दिखायी है, जिसके तहत 25.8 मिलियन आवेदन जमा किए गए हैं। इनमें से 2.37 मिलियन आवेदकों ने तीन-चरण की सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है।

इसके अलावा, लगभग 1 मिलियन पंजीकृत कारीगरों को ई-वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपये तक के टूलकिट प्रोत्साहन से लाभ हुआ है, जिससे वे अपने शिल्प कौशल में वृद्धि करने वाले आधुनिक उपकरण प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं।

पीएम विश्वकर्मा योजना की मुख्य बातें

- पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है, जिसका वित्तीय परिव्यय पांच साल (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपये है।
- विश्वकर्माओं को बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करते हुए सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क पंजीकृत किया जाता है।
- कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और एक आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाती है।
- उन्हें 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये (पहली किस्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किस्त) तक का गिरवी-मुक्त ऋण समर्थन प्राप्त होता है। भारत सरकार 8% की सीमा तक ब्याज अनुदान देती है और यह धनराशि बैंकों को अग्रिम रूप से प्रदान की जाती है। ■

प्रधानमंत्री ने 'डिजिटल अरेस्ट' फ्रॉड से बचने का दिया मंत्र– 'रुको, सोचो और एक्शन लो'

कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही पैसे की मांग करती है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 115वीं कड़ी में 27 अक्टूबर को कहा कि डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है।

उन्होंने कहा कि आप को पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी, फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के तीन चरण बताता हूं। ये तीन चरण हैं– 'रुको, सोचो, एक्शन लो'। कॉल आते ही, 'रुको'; घबराएं नहीं, शांत रहें, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें।

श्री मोदी ने कहा कि इसके बाद आता है, दूसरा चरण। पहला चरण था 'रुको', दूसरा चरण है 'सोचो'। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसे की मांग करती है; अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा— 'रुको', दूसरे चरण में मैंने कहा— 'सोचो' और तीसरा चरण कहता हूं— 'एक्शन लो'। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। 'रुको', बाद में 'सोचो' और फिर 'एक्शन' लो, ये तीन चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे।

आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, हमारा passion है

प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, हमारा passion बन गया है। बहुत साल नहीं हुए सिर्फ 10 साल पहले की बात है, तब अगर कोई कहता था कि किसी जटिल तकनीक को भारत में विकसित करना है तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो कई उपहास उड़ाते थे, लेकिन आज वही लोग देश की सफलता को देखकर अचंभे में रहते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर क्षेत्र में कमाल कर रहा है। आप सोचिए, एक जमाने में मोबाइल फ़ोन आयात करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा उपकरण खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को निर्यात भी कर रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान 'एक जन अभियान' बन रहा है, हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। जैसे इसी महीने लद्दाख के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी 'इमेजिंग टेलीस्कोप MACE' का भी उद्घाटन किया है। ये 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जानते हैं इसकी भी खास बात क्या है— ये 'मेड इन इंडिया' है। सोचिए, जिस स्थान पर माइनस 30 डिग्री की ठंड पड़ती हो, जहां ऑक्सीजन तक का अभाव हो, वहां हमारे वैज्ञानिकों और स्थानीय उद्योग ने वो कर दिखाया है, जो एशिया के किसी देश ने नहीं किया। हानले का टेलीस्कोप भले ही दूर की दुनिया देख रहा हो, लेकिन ये हमें एक चीज और भी दिखा रहा है और ये चीज है— 'आत्मनिर्भर भारत' का सामर्थ्य।

इस अवसर पर श्री मोदी ने यह भी कहा कि आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट, जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है, वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है। एनीमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है, जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है, जैसे इन दिनों VR टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। आप वर्चुअल टूर के माध्यम से अजंता की गुफाओं को देख सकते हैं, कोणार्क मंदिर के कॉरिडोर में टहल सकते हैं या फिर वाराणसी के घाटों का आनंद ले सकते हैं। ये सभी VR एनीमेशन भारत के क्रिएटर्स ने तैयार किए हैं।

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती

'मन की बात' की शुरुआत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पिछले साल 15 नवंबर को मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्मजयंती पर

उनकी जन्मस्थली झारखंड के उलिहातू गांव गया था। इस यात्रा का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं, जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला। उस क्षण मुझे न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की शक्ति महसूस हुई, बल्कि इस धरती की शक्ति से जुड़ने का भी अवसर मिला। मुझे ये एहसास हुआ कि कैसे एक संकल्प को पूरा करने का साहस देश के करोड़ों लोगों का भाग्य बदल सकता है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत में हर युग में कुछ चुनौतियां आईं और हर युग में ऐसे असाधारण भारतवासी जन्मे, जिन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया। आज की 'मन की बात' में मैं साहस और दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे ही दो महानायकों की चर्चा करूंगा। इनकी 150वीं जन्म जयंती को देश ने मनाने का निश्चय किया है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवम्बर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्मजयंती वर्ष शुरू होगा। इन दोनों महापुरुष ने अलग-अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विज़न एक था 'देश की एकता'।

मोदी सरकार 'साइबर सिक्योर भारत' के निर्माण के प्रति संकल्पित है: अमित शाह

'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 27 अक्टूबर को देशवासियों को 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के प्रति जागरूक किया। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि पुलिस, CBI, नार्कोटिक्स या RBI अधिकारी बनकर फ्रॉड करने वालों के द्वारा लोगों को वीडियो कॉल पर धमकाने के कई मामले सामने आए हैं।

श्री शाह ने कहा कि मोदी जी ने ऐसी धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताने के साथ-साथ देशवासियों को बताया कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से जांच नहीं करती। इस तरह की साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए मोदी जी ने 'रुको, सोचो और एक्शन लो' का मंत्र दिया और ऐसे मामले सामने आने पर इनकी जानकारी तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर या https://cybercrime.gov.in पर देने की अपील भी की। मोदी सरकार 'साइबर सिक्योर भारत' के निर्माण के प्रति संकल्पित है। ■

प्रधानमंत्री ने क्षय रोग के खिलाफ लड़ाई में भारत की प्रगति की सराहना की

देश में 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की उल्लेखनीय गिरावट

तपेदिक (टीबी) उन्मूलन की दिशा में भारत की समर्पित यात्रा को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है, जिसमें 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में उल्लेखनीय 17.7% की गिरावट आई है, यह दर वैश्विक औसत गिरावट 8.3% से दोगुनी है, जैसाकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अपनी वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 में बताया है। यह मील का पत्थर भारत के राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के प्रभाव को जाहिर करता है, जो एक व्यापक रणनीति है जो 2025 तक टीबी उन्मूलन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक निदान, निवारक देखभाल, रोगी सहायता और एक क्रॉस-सेक्टर साझेदारी है।

क्षय रोग उन्मूलन में भारत के प्रयासों को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन नवंबर को क्षय रोग (टीबी) के मामलों में कमी लाने के संबंध में देश की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2015 से 2023 के दौरान क्षय रोग के मामलों में 17.7 प्रतिशत तक की कमी लाने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को मान्यता दिए जाने से संबंधित केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा के एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, "सराहनीय प्रगति! टीबी के मामलों में कमी भारत के समर्पित और अभिनव प्रयासों का परिणाम है। सामूहिक भावना के माध्यम से हम टीबी मुक्त भारत की दिशा में काम करते रहेंगे।"

उल्लेखनीय है कि '2025 तक टीबी को समाप्त करने' के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मार्च, 2018 में नई दिल्ली में आयोजित 'टीबी समाप्त शिखर सम्मेलन' के दौरान व्यक्त किया था और विश्व टीबी दिवस 2023 पर वाराणसी में 'एक विश्व टीबी शिखर सम्मेलन' में इसकी पुष्टि की गई थी। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने टीबी के लिए निर्णायक और पुनर्जीवित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, भारत गांधीनगर घोषणापत्र का भी हस्ताक्षरकर्ता है, जो स्वास्थ्य मंत्रियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय का संयुक्त घोषणापत्र है, जिस पर अगस्त, 2023 में दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में 2030 तक 'टीबी को समाप्त करने के लिए निरंतरता, गति और नवाचार' पर उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक में हस्ताक्षर किए गए थे।

कोविड-19 महामारी के बाद भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से टीबी को खत्म करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया, जो राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) 2017-25 के साथ जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है। 2023 में प्रमुख उपलब्धियों में लगभग 1.89 करोड़ स्पुतम स्मीयर परीक्षण और 68.3 लाख न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन परीक्षण शामिल हैं, जो सभी स्वास्थ्य सेवा स्तरों पर निदान तक पहुंच का विस्तार करने के लिए कार्यक्रम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ■

प्रधानमंत्री ने गुजरात के कच्छ में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ मनाई दीपावली

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अक्टूबर को गुजरात के कच्छ में सर क्रीक क्षेत्र के लक्की नाला में भारत-पाक सीमा के निकट सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सेना, नौसेना और वायु सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। श्री मोदी ने भारत के सशस्त्र बलों के साथ त्योहार मनाने की अपनी परंपरा को जारी रखा।

प्रधानमंत्री ने क्रीक क्षेत्र में एक बीओपी का भी दौरा किया और बहादुर सुरक्षाकर्मियों को मिठाइयां वितरित कीं। श्री मोदी ने सुरक्षाकर्मियों के साथ सर क्रीक में दिवाली मनाने को अपना सौभाग्य बताया और सभी को त्योहार की हार्दिक बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "कच्छ के क्रीक क्षेत्र में लक्की नाला में बीएसएफ, सेना, नौसेना और वायु सेना के हमारे बहादुर कर्मियों के साथ दिवाली मनाकर बहुत खुशी हुई। यह क्षेत्र चुनौतीपूर्ण और दूरस्थ दोनों है। दिन बहुत गर्म होते हैं और ठंड भी पड़ती है। क्रीक क्षेत्र में अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां भी हैं।''

उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षाकर्मी दुर्गम स्थानों पर भी डटे रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। हमें उन पर बहुत गर्व है। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

कजान (रूस) में 23 अक्टूबर, 2024 को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान समूह चित्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कजान (रूस) में 22 अक्टूबर, 2024 को ब्रिक्स नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते रूसी संघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन

कजान (रूस) में 23 अक्टूबर, 2024 को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

वडोदरा (गुजरात) में 28 अक्टूबर, 2024 को सी–295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज

हैदराबाद हाउस (नई दिल्ली) में 25 अक्टूबर, 2024 को जर्मनी के चांसलर श्री ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 19 नवंबर, 2024
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

दीपावली के अवसर पर भव्य, दिव्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाले अयोध्याधाम का दृश्य!

नरेन्द्र मोदी ऐप !!

प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ने के लिए
1800-2090-920
पर मिस कॉल करें!

पहचान: अपने काम को पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ साझा करें और अपनी पहचान बनायें।

सशक्तिकरण: कार्यों को प्रभावी ढंग और कुशलता से पूरा करके अपनी क्षमता का अनुभव करें।

नेटवर्किंग: पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ जुड़ें जो अच्छा काम कर रहे हैं।

सहभागिता: समावेशी विकास को शक्ति प्रदान करने वाले विचारों और प्रयासों की सामूहिक शक्ति का लाभ उठाएं।

इस QR कोड को स्कैन करके नमो ऐप को डाउनलोड करें।

नमो ऐप के संबंध में नवीनतम जानकारी पाएं। (QR कोड स्कैन करें)

NARENDRA MODI APP

E-books | India Positive | Info-in-graphics | Kashi Vikas Yatra | Mann ki Baat | Media Coverage | Mera Saansad | Vikas Yatra | Your Voice

#HamaraAppNaMoApp

छायाकार: अजय कुमार सिंह